सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 36 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 19 नवंबर 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

किसानों को बड़ी सौगात : जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को 'स्थानीयकृत जोखिम' के रूप में दी मान्यता

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसानों के हित में निर्णय

नईदिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई-बहनों को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पांचवें 'ऐड-ऑन कवर' के रूप में मान्यता दी गई है।

राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और किसानों को गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रक्रियाएं PMFBY परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाई गई हैं, और खरीफ2026 से पूरे देश में लागू की जाएगी।

देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यत: वन क्षेत्रों, वन गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। दूसरी ओर, तटीय एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले किसानों को वर्षा और नदी-नालों के उफान से होने वाले जलभराव के कारण समान रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता रहा है। वर्ष 2018 में इस जोखिम को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी से हटाए जाने से किसानों के लिए एक बड़ा संरक्षण अंतर उत्पन्न हो गया था।

नुकसान झेलने वाले किसानों को समय पर मिलेगा निपटान का लाभ

इन चुनौतियों को देखते हुए विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को PMFBY के तहत समय पर दावा निपटान का लाभ मिलेगा। इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा। धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुन: शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन्हें शमिल किए जाने से PMFBY और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और किसान हितैषी बन गया है, जो भारत की फसल बीमा प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं लचीला बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

खास-खबर

पॉक्सो एक्ट के आरोपी नाबालिग की मां का आरक्षक पर गंभीर आरोप

बजरंग दल ने थाने का घेराव कर की आरक्षक के गिरफ्तारी की मांग

भिलाई। भिलाई-3 में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला पॉक्सो एक्ट के आरोपी नाबालिग बेटे को लिखा पढ़ी में मदद करने के बदले में पुलिस आरक्षक ने उसकी मां से अपना शरीर सौंपने का ऑफर दिया। महिला के आरोप में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो जांच में चलेगा। लेकिन मामले ने आज अच्छा खासा तुल पकड़ लिया है। महिला के पक्ष में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज भिलाई-3 थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफकार्रवाई करने को लेकर जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की है।

इस मामले में पीड़िता महिला भिलाई-3 थाना क्षेत्र के डबरा पारा की रहने वाली बताई जा रही है। महिला के पति के निधन हो चुका है। कुछ दिन पहले पुलिस ने महिला के नाबालिग बेटे पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किया है। महिला का आरोप है कि उसने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भिलाई-3 थाने में पदस्थ एक आरक्षक से मदद मांगी। इसके लिए उसने आरक्षक का मोबाइल नंबर लिया और उसे अपना नंबर दिया। आरक्षक ने बेटे को छुड़ाने के बदले अपने साथ एक रात बिताने को कहा। इतना ही नहीं कल 18 नवंबर को आरक्षक ने प्रेशर बनाकर महिला को सिरसा गेट चौक पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। महिला का आरोप है कि उसने साफइंकार किया। उसके द्वारा पीरियड चलने की जानकारी देने पर आरक्षक ने प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाकर देखा। महिला ने इस बात की जानकारी बजरंग दल की महिला नेत्री ज्योति शर्मा को दी। जिसके बाद आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफकार्रवाई करने की मांग रखी। इस दौरान वाट्सएप चैटिंग और बातचीत का आडियो पुलिस को सौंपे जाने की चर्चा है। समाचार लिखे जाने तक एडिशनल एसपी आईयूसीएडब्ल्यू पद्मश्री तंवर और टीआई अम्बर सिंह भारद्वाज इस मामले पर आरोप लगाने वाली महिला व बजरंग दल कार्यकर्ताओं से चर्चा करते रहे।

एक दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ

छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को राहत : 400-500 रुपए हर महीने बचेंगे, 4 महीने में दूसरी बार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफयोजना की घोषणा कर दी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब 200 यूनिट पर 800-900 रुपए तक आने वाला बिल अब 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसका ऐलान किया। सीएम ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना लागू होगी। योजना के तहत 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफबिजली का लाभ मिलेगा। इससे 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे।

बता दें भूपेश सरकार ने 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता था, तो उसे कुल बिल का सिर्फआधा भुगतान करना होता था। 4 महीने पहले यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफयोजना पर बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव का असर सीधे-सीधे लाखों परिवारों पर पड़ा था। बिल लगभग डबल हो गया था। योजना में कटौती के बाद कांग्रेस ने लगातार विरोध जताया था। कई जिलों में उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिलों के खिलाफप्रदर्शन भी किया था। वहीं, छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका आर्थिक असर साफ दिखने लगा था। सरकार के भीतर भी यह महसूस किया गया उपभोक्ताओं को राहत देना जरूरी है।

उदाहरण के साथ समझिए बिजली बिल हाफ योजना

अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल अभी लगभग 840 से 870 रुपए के बीच आता है। इसमें पहले 100 यूनिट का रेट 4.10 प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का रेट 4.20 प्रति यूनिट है। अब नई योजना के तहत सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिल स्कीम लागू कर रही है। यानी उपभोक्ता को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट का बिल ?410 से ?450 तक होता है, जो अब आधा होकर 205 से 225 के बीच रह जाएगा। दूसरे 100 यूनिट (100-200) के लिए बिल 840 से 870 तक आता है, जो अब समान रहेगा, क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में ही है। कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को लगभग 420 से 435 की सीधी राहत मिलेगी। यानी जो उपभोक्ता पहले 1250-1300 तक का बिल देते थे, अब उन्हें सिर्फ 800-850 का ही बिल चुकाना पड़ेगा।

विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम साय ने लिया निर्णय

घरेलू उपभोक्ताओं को जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है उन्हें 200 यूनिट तक हाफबिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस निर्णय से राज्य के 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफबिजली बिल का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इस तरह 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के 45 लाख उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर उपभोक्ता को सस्ती, सुचारू और भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। सोलर प्लांट स्थापना प्रक्रिया में समय लगने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना लागू की जा रही है, जिससे आम जनता के बिजली बिल में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

जनता को राहत पर विभाग पर बढ़ेगा अतिरिक्त भार

सरकार का नया मसौदा लागू होते ही राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर पड़ रहा दबाव कम होगा। बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित रूप से हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआईएस से जुड़े रायपुर व भिलाई के दो आरोपी हिरासत में

■ स्थापना के बाद एटीएस ने दर्ज की पहली एफआईआर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंध के चलते रायपुर व भिलाई से दो किशोरों को हिरासत में लिया है। आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) ने इनकी पहचान की है, जिनसे पाकिस्तान स्थित आईएसआईएस के हेंडलर्स ने इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया था। जांच में पता चला कि पाकिस्तान स्थित आईएसआईएसमॉड्यूल भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा है। इस मामले में एटीएस ने संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, 1967 के तहत सोमवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज की है।

एटीएस ने जिन 2 नाबालिगों की पहचान की गई है। उसमें एक रायपुर और दूसरा भिलाई का रहने वाला है। इनकी उम्र 16 और 17 साल बताई जा रही हैं। खुफिया एजेंसी करीब डेढ़ साल से इन पर नजर बनाई हुई थी। जांच एजेंसियों को इनके पास मिले मोबाइल से कई कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले मैसेज और वीडियो संदेश मिले हैं। आईएसआईएस इन नाबालिगों के जरिए से अंदरूनी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था।

फर्जी अकाउंट से युवाओं को बरगलाया जा रहा था

एटीएस के अनुसार इंस्टाग्राम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट से लगातार युवाओं को जोड़कर उकसावे, कट्टरपंथी प्रचार और जिहादी विचारधारा का प्रसार किया जा रहा था। हैंडलर भारतीय किशोरों को ग्रुप चैट में शामिल कर उनको कट्टरपंथी विचारधारा के लिए भड़का रहे थे। इसके अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ में ड्डस्ड्ड का मॉड्यूल खड़ा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। 2017 में एटीएस की स्थापना के बाद यह पहली एफआईआर हैं।

डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसकी देते हुए बताया कि राज्य में यह इस तरह का पहला मामला है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ऐसे और भी लोग हैं। विजय शर्मा ने बताया कि गहन जांच के बाद एटीएस ने उन दोनों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ये दोनों पाकिस्तान स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल के निर्देशों पर काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए सक्रिय थे। उन्होंने कहा, 'वे चरमपंथी सामग्री से स्वयं प्रभावित थे और इंस्टाग्राम पर दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास पर्याप्त जानकारी थी और वे आईएसआईएस के नाम पर इंटरनेट व सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग कर रहे थे।' शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की सूचना तुरंत पुलिस को दें जो देशविरोधी सामग्री फैला रहा हो।

दूसरे दिन भी सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी सात माओवादी ढेर, 50 से ज्यादा गिरफ्तार

अमरावती। आंध्र प्रदेश में खूंखार माओवादी माड़वी हिड़मा के मारे जाने के एक दिन बार भी सुरक्षाबलों की कार्रवाई जी है। बताया गया है कि राज्य के मारेदुमिल्ली इलाके में हुई मुठभेड़ में सात माओवादी मार गिराए गए। आंध्र प्रदेश खुफिया विभाग के एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिन माओवादियों की जान गई है, उनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। सभी की पहचान की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, मारा गया एक माओवादी मेतुरी जोखा राव उर्फशंकर था। वह श्रीकाकुलम का रहने वाला था और आंध्र-ओडिशा बॉर्डर के लिए जिम्मेदारी देख रहा था। वह तकनीकी मामलों का जानकार था। साथ ही हथियारों, संचार से जुड़ी चीजों पर भी उसकी अच्छी पकड़ थी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 50 भाकपा

(माओवादी) कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन कृष्णा, एलुरु, एनटीआर विजयवाड़ा, काकिनाड़ा और डॉ. बीआर आंबेडकर कोणासीमा जिले में चलाए गए। इससे माओवादी संगठन के दक्षिण बस्तर और दंडाकरन्या नेटवर्क पर गहरी चोट हुई है। पुलिस के मुताबिक, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें वरिष्ठ माओवादी, संचार मामलों के जानकार, सशस्त्र प्लाटून सदस्य और पार्टी के लोग शामिल हैं। यह सब लोग करीब से माड़वी हिड़मा के साथ काम कर रहे थे, जो कि भाकपा-माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति का सदस्य था।

क्यों आ जाता है एमपी-ओड़ीशा से धान

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने धान खरीदी में लगे सभी लोगों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। छुट्टी लेने वालों तथा कामकाज में लापरवाही बरतने वालों पर निलंबन और बरखास्तगी की तलवार लटक रही है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर पुलिस दिन-रात गश्त कर रही है। भारी मात्रा में धान पकड़ा भी जा रहा है। मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़, ओड़ीशा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश, चारों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं। चारों राज्यों में धान की खेती का खर्च भी लगभग समान है। बावजूद इसके मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओड़ीशा में खरीफविपणन सत्र 2025-26 के लिए, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 2389 प्रति क्विंटल है। जबकि छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल है। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य के किसान अपना धान छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश करते हैं। किसान ही क्यों, किसी भी व्यापारी को अपने उत्पाद का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करने का नैतिक और बुनियादी अधिकार है। इसीलिए पड़ोसी राज्यों के किसान अपना धान छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश करते हैं। दरअसल, सत्ता हासिल करने के लिए वोट बैंक बनाना एक राजनीतिक मजबूरी है। पहले तो केवल चुनाव से ऐन पहले शराब, साड़ी और पैसा बांटने का चलन था। पर अब इसे भी वैधानिक जामा पहना दिया गया है। अब पार्टियां लुभावने वायदे के साथ चुनाव लड़ती हैं और फिर जीतने के बाद आनन फानन में अपने वादों को पूरा करने में जुट जाती हैं। ऐसी खबरें देशभर में आम हैं कि सरकार बनाते ही साथ एक वायदा पूरा कर दिया, 15 दिन में तीन वायदे पूरे कर दिए या साल-छह महीने में घोषणा पत्र के आधे से ज्यादा वायदों को पूरा कर दिया गया। कुछ ही समय पहले तक मामूली सहूलियात देने पर सरकार पर आरोप लग जाया करता था कि वह रेवड़ी बांट रही है। वही रेवड़ी अब पूजा में फूलमाला और प्रसाद की तरह जरूरी हो गया है। रेवड़ियां बांटना अब ऑफीशियल हो चुका है। भले ही इसके बोझ तले सरकार की कमर टूट जाए। उसका खजाना खाली हो जाए। पर जनता को खुश रखना जरूरी है। कभी अल्पसंख्यकों, कभी पिछड़ा वर्गों तो कभी बहुसंख्यक आबादी को लुभाने की कोशिशें इसी वोट बैंक पॉलिसी की देन है। यही कारण है कि अब सरकार के कामकाज की कोई चर्चा नहीं करता। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे जरूरी मुद्दों पर भी जनता बंटी हुई नजर आती है। जनता की इस बेहिसी का असर अखबारों पर भी हुआ है। उन्हें भी अब इन मुद्दों पर लिखना पढ़ना बेमानी लगने लगा है। अखबार पाकिस्तान और बांग्लादेश की फटेहाली की कहानियां छापकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। धान के मामले में तो समस्या बोती सरकार है और इसका ठीकरा उसके अदना कर्मचारियों के सिर फूटता है।

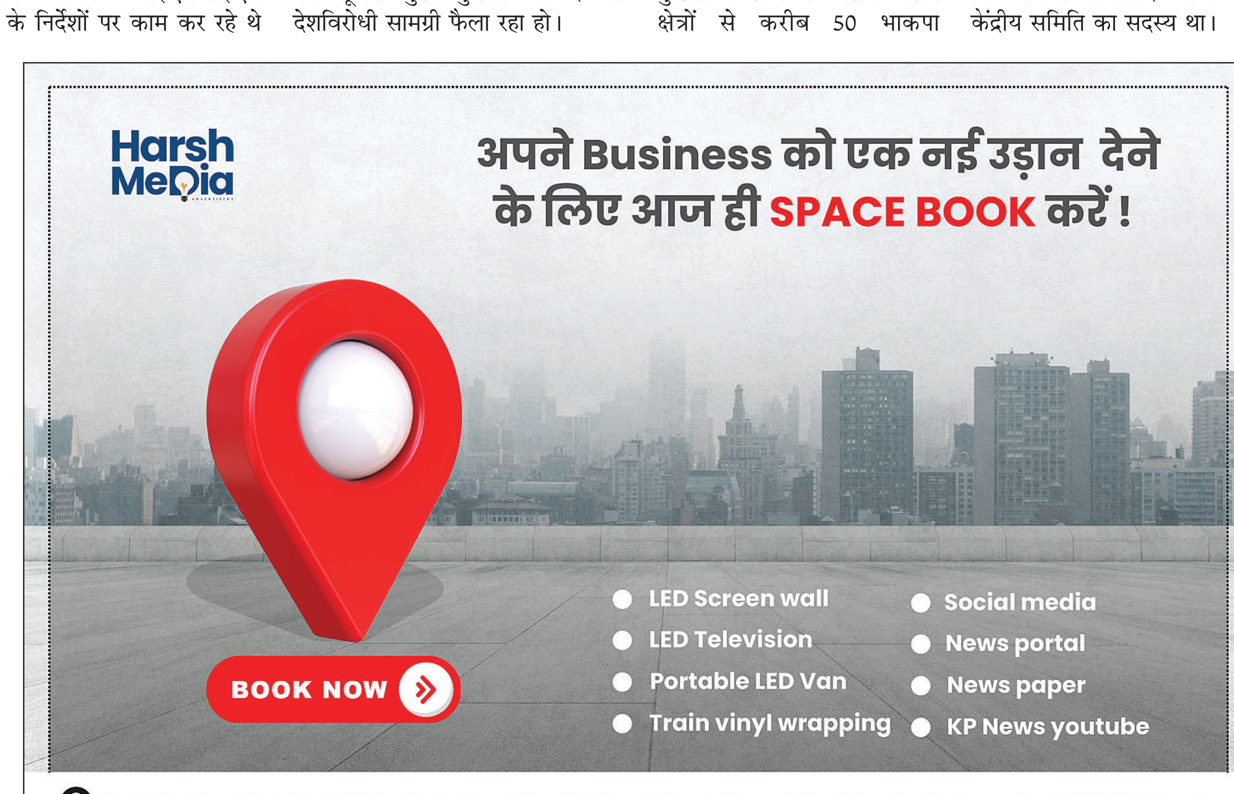

संपादकीय

नाबालिगों के अपराध

स्पष्ट कानून व सज़ा में बदलाव से समाधान

हाल ही में, दिल्ली के विजय विहार इलाके में लूट का विरोध करने वाले एक ऑटो चालक की निर्मम हत्या में पांच नाबालिगों की गिरफ्तारी गंभीर चिंता बढ़ाने वाली है। देश में नाबालिगों के बालिगों की तर्ज पर गंभीर अपराधों को अंजाम देने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली की घटना में गिरफ्तार किशोरों की स्वीकारोक्ति डराने वाली है कि वे नशे के आदी हैं और पैसे जुटाने के लिये लूटपाट जैसे अपराधों में लिप्त रहते हैं। यह घटना हमारे समाज में पनप रही विकृतियों की ओर इशारा कर रही है। साथ ही यह भी संकेत कि अब वक्त आ गया है कि किशोर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये सख्त कानूनों के प्रावधान हों। इसकी वजह यह है कि किशोरों को अपराध करने के बाद सामान्य जेलों में रखने के बजाय बाल सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। लेकिन बाल सुधार गृहों में रहने के दौरान भी ऐसे अपराधी किशोरों में बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। अक्सर देखा जाता है कि बाल सुधार गृहों में रहने की सीमित अवधि के बाद कई किशोर फिर अपराधों की दुनिया में उतर जाते हैं। समाज विज्ञानियों का मानना है कि किशोर अपराधों को लेकर कानून के अस्पष्ट और लचर होने की वजह से भी दोषियों को दंडित नहीं किया जा सकता। अक्सर कहा जाता है कि नाबालिगों की सजा के मामले में अभियुक्त की उम्र को घटा दिया जाए। दरअसल, बदलते परिवेश में समय से पहले किशोरों में वयस्कों की नकारात्मक प्रवृत्तियां पनपने लगी हैं। जिसके चलते वे बड़ों के जैसे अपराध तो करते हैं। लेकिन उन्हें उस अनुपात में सजा नहीं दी जा सकती। वैसे यह भी हकीकत है कि किशोरों के सामने लंबा भविष्य होता है। यदि परिस्थितिवश या मजबूरी में वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। वैसे भी दंड का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति में सुधार ही होता है।

> “ ऐसे में नशे पर अंकुश के साथ ही उन सामाजिक विसंगतियों पर नजर रखने की जरूरत है जो किशोर मन के भटकाव को जन्म देती हैं। दूसरा संकट भारतीय समाज में जीवन मूल्यों का तेजी से होता पराभव भी है। किशोरों को नैतिक शिक्षा का पाठ सही ढंग से न स्कूलों में मिल पा रहा है और न ही घरों में।

दरअसल, इस तथ्य पर भी विचार करने की जरूरत है कि यदि किशोर सजा काटने के बाद भी लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहते हैं तो उसके लिये दंड के सख्त प्रावधान होने चाहिए। वहीं, अपराध के मूल में आर्थिक विषमताएं भी हैं, जिसके चलते वे पढ़-लिख नहीं पाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में तमाम सामाजिक विद्रूपताएं भी किशोर मन में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जैसेकि दिल्ली की घटना में लिप्त किशोरों ने स्वीकारा कि वे नशे के आदी हैं, यह घटना हमारे समाज में नशे के नासूर से उपजे संकट की ओर इशारा करती है। ऐसे में नशे पर अंकुश के साथ ही उन सामाजिक विसंगतियों पर नजर रखने की जरूरत है जो किशोर मन के भटकाव को जन्म देती हैं। दूसरा संकट भारतीय समाज में जीवन मूल्यों का तेजी से होता पराभव भी है। किशोरों को नैतिक शिक्षा का पाठ सही ढंग से न स्कूलों में मिल पा रहा है और न ही घरों में। इस संकट का एक बड़ा पहलू इंटरनेट पर जहरीली व अश्लील सामग्री की प्रचुरता भी है। अक्सर किशोरों व वयस्कों के अपराधों के कारण जानने पर पता चला कि उन्होंने इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने के बाद यौन हिंसा को अंजाम दिया। ऐसे में बच्चों को संस्कार स्कूल और घर के बजाय मोबाइल से मिल रहे हैं। इंटरनेट पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को कौन और किस उद्देश्य से डाल रहा है, कहना कठिन है। लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया व इंटरनेट से जुड़े विभिन्न माध्यमों में परोसी जा रही विषैली सामग्री बाल मन पर बुरा असर डाल रही है। ऐसे में नशा, अश्लीलता और अपराध उन्मुख कार्यक्रम किशोरों को अपराध की गलियों में गुजरने के लिए उकसा रहे हैं। बहरहाल, अब समय आ गया है कि नीति-नियंताओं को विचार करना चाहिए कि हत्या-बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों के लिये कैसे कानून बनें। निश्चय ही कानून का मकसद किसी अपराधी में सुधार ही होना चाहिए। लेकिन इस छूट को सजा से छूट का हथियार बनने देने से भी रोकना चाहिए। अन्यथा किशोरों के अपराधों का सिलसिला बेकाबू हो सकता है।

बिहार का जनादेश और भारतीय राजनीति का उभरता परिदृश्य

हरदीप सिंह पुरी

बिहार की जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया है, जिसका महत्व सीटों के गणित से कहीं आगे जाता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने विधानसभा की 243 सीटों में से 202 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 89 सीटें हासिल की हैं, जो राज्य में पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दशकों तक विभिन्न गठबंधनों के तहत बिहार की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखने के बाद, महागठबंधन अब सिर्फ़ 34 सीटों पर सिमट गया है। 7.4 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत मतदाताओं में से 67.13 प्रतिशत ने मतदान किया। यह चुनाव राज्य के हाल के इतिहास में सबसे कड़े मुक़ाबले वाले चुनावों में से एक सिद्ध हुआ है और चुनाव परिणामों ने वास्तविक लोकतांत्रिक गहराई को रेखांकित किया है। वर्षों तक, बिहार पर व्यक्त किये गए विचारों में राज्य को समय के प्रवाह में एक रुका हुआ राज्य मान लिया गया था। चुनावों को जातिगत अंकगणित की कवायद माना जाता था और सामाजिक जनसांख्यिकी को राजनीतिक नतीजों में तब्दील कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय राजनीति का परिदृश्य निर्णायक रूप से विकास, समावेश और राज्य क्षमता के रूप में बदल गया है तथा बिहार के मतदाताओं ने इस बदलाव को लेकर पूरी स्पष्टता से जवाब दिया है। 2025 के परिणाम एक ऐसे मतदाता को इंगित करते हैं, जिसकी आकांक्षा बड़ी है और जिसने असुरक्षा व पक्षाघात वाले बिहार तथा बेहतर शासन वाले बिहार के बीच के अंतर को महसूस किया है। कई नागरिकों ने बातचीत में और मतदान के पैटर्न में व्यक्त किया है कि 2024 के आम चुनाव में अपेक्षा से कम समर्थन के बाद यह चुनाव जिम्मेदारी की भावना लेकर आया है। लोगों ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं कि वे देश की व्यापक यात्रा में बिहार को कहाँ देखना चाहते हैं। बेहतर शासन ने इस परिवर्तन को आधार प्रदान किया है। पिछले एक दशक में, बिहार में 55,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण या उन्नयन हुआ है, जो गांवों को बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ती हैं। केंद्रीय योजनाओं और राज्य कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से लाखों परिवारों को बिजली, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। सौभाग्य और उससे जुड़ी पहलों के तहत, बिहार में 35 लाख से ज़्यादा घरों का

विद्युतीकरण किया गया, जिससे राज्य सार्वभौमिक घरेलू बिजली आपूर्ति के करीब पहुँच गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बिहार के लिए 57 लाख से ज़्यादा पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से कई महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। ये आँकड़े उन ठोस बदलावों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें लोग देख और अनुभव कर सकते हैं- एक बारहमासी सड़क, एक जलती रहने वाली रोशनी, एक नियमित पेयजल आपूर्ति करने वाला नल तथा एक ऐसा घर, जो सम्मान प्रदान करता हो। जैसे-जैसे इन सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, पुरानी शक्तियों की पकड़ ढीली होती गयी। बिहार का समाज विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय है, फिर भी चुनावी लिहाज़ से यह बहुस्तरीय समाज अपने समुदायों तक सीमित नहीं रहा। विभिन्न समुदायों की महिलाएँ अब सुरक्षा, आवागमन और अवसर को लेकर एक जैसी अपेक्षाएँ रखती हैं। कभी सामाजिक पदानुक्रम के विपरीत छोर पर खड़े परिवारों के युवा अब खुद को एक ही कोचिंग क्लास और श्रम बाज़ार में पाते हैं। उनके रोज़मर्रा के अनुभव उन्हें आकांक्षाओं के एक साझा दायरे में ले आते हैं। उस दायरे में, वे राजनीति से रोज़गार, अवसंरचना, स्थिरता और निष्पक्षता जैसे सवाल पूछते हैं।

इस जनादेश ने वंशवाद-केंद्रित राजनीति पर भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। पारिवारिक करिश्मे और विरासत में मिले नेटवर्क पर निर्भर रहने वाली पार्टियों का विधायी दायरा तेज़ी से सिकुड़ रहा है। बिहार ने कई दशकों से ऐसे गठबंधनों को करीब से देखा है और उनकी सीमाओं को समझा है। 2025 के नतीजे बताते हैं कि मतदाता इस बात पर गौर कर रहे हैं कि नेता सरकार में कैसा व्यवहार करते हैं, संकट के समय में उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, संस्थाओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों का किस रूप में उपयोग करते हैं। व्यापक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पारिवारिक पृष्ठभूमि मौजूद है, लेकिन वहाँ भी कड़ी मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और सेवा के रिकॉर्ड से जुड़ी माँगें उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं।

युवा मतदाताओं का व्यवहार इस बदलाव का मूल तत्व है। बिहार भारत की सबसे युवा जनसांख्यिकीय आबादी वाले राज्यों में से एक है और 2000 के बाद जन्म लिए लाखों नागरिकों ने इस चुनाव में मतदान किया है। वे ऐसे भारत में पले-बढ़े हैं जहाँ एक्सप्रेसवे, डिजिटल भुगतान, प्रतिस्पर्धी संघवाद और महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाएँ अपेक्षाओं को आकार देती हैं। वे राज्यों की तुलना करते हैं, घोषणाओं पर नज़र रखते हैं और नेताओं का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वादे कितनी तेज़ी से कार्यान्वित होते हैं। उनके लिए, समय पर बनी सड़क और कभी फ़ाइल से बाहर न आने वाली सड़क के बीच का अंतर समझना कोई कठिन बात नहीं है। वे हर दिन उस अंतर का अनुभव करते हैं जब वे कॉलेजों, कोचिंग सेंटर या कार्यस्थलों पर आते-जाते हैं, या जब वे अपने परिवारों को परिवहन संपर्क-सुविधा और कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होते देखते हैं।

यह पीढ़ी राष्ट्रीय एकजुटता के लिए भी एक तीव्र प्रवृत्ति रखती है। युवा मतदाता ऐसी बयानबाजी के प्रति सतर्क रहते हैं, जो संस्थानों को कमज़ोर करती हैं, अलगाववादी भावनाओं को भड़काती हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा को कम महत्व देती हैं। वे बेरोज़गारी और असमानता सहित नीतिगत बहसों में आलोचनात्मक रूप से शामिल होते हैं, फिर भी वे गणतंत्र को बेहतर बनाने वाली आलोचना और देश की एकजुटता के प्रति उदासीन आख्यानों के बीच एक रेखा खींचते हैं। बिहार का जनादेश इसी अंतर को प्रतिबिंबित करता है। मतदाताओं ने एक ऐसे राजनीतिक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है, जो विकास और राष्ट्रीय उद्देश्य दोनों को असाधारण स्पष्टता के साथ व्यक्त करता है। कानून-व्यवस्था एक अन्य व्याख्या प्रस्तुत करती है। बिहार के चुनाव कभी बूथ कब्जे और

हिंसा से जुड़े होते थे। हाल के वर्षों में, और खासकर इस चुनावी दौर में, ये छवियाँ काफी हद तक धुंधली पड़ गई हैं। कड़े सुरक्षा उपायों और आर्थिक विकास के संयुक्त प्रभाव से उग्रवाद कमजोर पड़ा है। व्यापारी अब अपनी दुकानें ज़्यादा देर तक खुली रखते हैं, छात्र ज़्यादा आत्मविश्वास से यात्रा करते हैं और परिवार निश्चिंत होकर सार्वजनिक जीवन का अनुभव करता है। जिस मतदाता ने इन सुधारों को देखा है, वह अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय

इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। इन घटनाक्रमों पर विपक्ष के कुछ हिस्सों की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली रही है। अपने समर्थन में आई कमी के कारणों पर विचार करने के बजाय, कुछ नेता चुनाव आयोग, मतदाता सूचियों या पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही संदेह व्यक्त कर रहे हैं। यह रवैया बिहार के मतदाताओं की बुद्धिमत्ता के साथ न्याय नहीं करता। यह इस तथ्य की भी अनदेखी करता है कि इसी संस्थागत व्यवस्था ने अन्य राज्यों में विपक्ष के पक्ष में भी नतीजे दिए हैं। मतदाता उस व्यवस्था की निंदा करने के बजाय अपनी चिंताओं के साथ अधिक गंभीर जुड़ाव की अपेक्षा करता है जिसका उसने अभी इतने उत्साह से इस्तेमाल किया है। व्यापक राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ में, बिहार का जनादेश एक उभरते हुए पैटर्न को मजबूत करता है। ऐसे समय में जब कई लोकतंत्र ध्रुवीकरण, आर्थिक कठिनाई और संस्थागत थकान से जूझ रहे हैं, भारत ने उच्च भागीदारी, स्थिर नेतृत्व तथा विकास, समावेश और राष्ट्रीय

शक्ति पर केंद्रित नीति मार्ग पर आगे बढ़ना जारी रखा है। बिहार के परिणाम, इस विकास-पथ के लिए लोकतांत्रिक समर्थन की एक और परत जोड़ते हैं। राजनीतिक रूप से भारत के सबसे जागरूक राज्यों में से एक के मतदाता महसूस करते हैं कि उनकी प्रगति, 2047 तक एक विकसित और आत्मविश्वास से भरे भारत की ओर देश की बड़ी यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए यह जनादेश प्रोत्साहन और निर्देश दोनों है। यह अवसंरचना, कल्याणकारी सेवा अदायगी और सुरक्षा पर जोर को मान्यता देता है, लेकिन यह तेजी से रोजगार सृजन, गहन सुधारों और निरंतर संस्थागत सुधार की उम्मीदों को भी सामने रखता है। विपक्ष के लिए, यह जनादेश रणनीति, नेतृत्व और कार्यक्रम के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। बिहार के मतदाताओं ने संकेत दिया है कि वे शासन, गंभीरता और राष्ट्रीय एकता के प्रति सम्मान पर आधारित राजनीति की उम्मीद करते हैं। ये उम्मीदें आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का परिदृश्य तय करेंगी।

महिला आरक्षण की बहस

बिना आर्थिक भागीदारी बढ़ाए और सामाजिक परिवेश बदले सिर्फ राजनीति प्रतिनिधित्व देना प्रतीकात्मक महत्त्व भर का साबित हो सकता है। ऐसी अनेक मिसालें अभी मौजूद हैं। अत: महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा फ़लक दिए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ‘सबसे बड़ी अल्पसंख्यक’ बताया है। अगर इसका अर्थ निर्णय के स्थलों और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उपस्थिति से है, तो कोर्ट की राय से सहज सहमत हुआ जा सकता है। वैसे ये टिप्पणी करते हुए जस्टिस बी।वी। नागरत्नम्मा ने आबादी में महिलाओं की संख्या का भी जिक्र किया। कहा कि कुल आबादी में महिलाएं 48।44 फीसदी हैं। यानी संख्यात्मक रूप से भी वे अल्पसंख्यक हैं। जस्टिस नागरत्नम्मा ने कहा कि संविधान में 106वां संशोधन महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने की मिसाल है, हालांकि उन्होंने सवाल किया कि आखिर आरक्षण के प्रावधान से अलग भी राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस नागरत्नम्मा और जस्टिस आर। महादेवन की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हुए संविधान संशोधन से संबंधित है। चूंकि उपरोक्त आरक्षण जनगणना के बाद होने वाले चुनाव में लागू होगा, तो इस कथित देर पर याचिका में सवाल खड़े किए गए हैं। मगर कोर्ट इस देर से अधिक परेशान नहीं दिखा। इसी क्रम में बिना आरक्षण लागू हुए प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया गया। बहरहाल, प्रतिनिधित्व अभी मिले या जनगणना के बाद कुछ अहम सवाल कायम रहेंगे। इनमें प्रमुख यह है कि प्रतिनिधित्व दिखावटी होना चाहिए या यह वास्तविक सशक्तीकरण का परिणाम होना चाहिए? आरक्षण के प्रावधान अक्सर वंचित या पीड़ित समूहों की स्व-प्रेरणा एवं अपनी शक्ति से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं।

संभव है कि यही बात महिला आरक्षण के संदर्भ में भी लागू होती दिखे। सत्ता के ऊंचे स्थलों पर महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम है, तो उसका कारण वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरातल है, जिसमें बच्चियों को लड़कों से कमतर अवसर मिल पाते हैं। खुद जस्टिस नागरत्नम्मा ने भी कहा कि राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का समान महत्त्व है। तो बिना आर्थिक भागीदारी बढ़ाए और सामाजिक परिवेश बदले सिर्फ राजनीति प्रतिनिधित्व देने की कोशिश प्रतीकात्मक महत्त्व की साबित हो सकती है। फिलहाल, ऐसी अनेक मिसालें भारतीय राजनीति में मौजूद हैं। अत: महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा दायरा दिए जाने की जरूरत है।

असली खेल जाति की राजनीति का था

हरिशंकर व्यास

बिहार में अगर एक तरफ ‘मुफ्त की रेवड़ी’ की बहार थी तो दूसरी ओर जाति राजनीति का दांव था। इसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने दोनों को बराबर साधा। सरकारी खजाने से नकद पैसे और मुफ्त की सेवाएं बांट कर सरकार के प्रति बन रही नाराजगी को दूर किया गया। यह एनडीए के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती थी कि नीतीश कुमार की सत्ता 20 साल की हो गई और लगातार 20 साल सरकार में रहने की वजह से कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी है या थकान और उब है। इसको दूर करने के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा कर चार सौ से 11 सौ रुपए की गई और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। असल में इन तमाम योजनाओं के जरिए नीतीश या मोदी को कोई नया वोट नहीं जोड़ना था। उनको अपने पुराने वोट को साथ में बनाए रखना था। उनको पता था कि यह वोट जातिगत आधार पर या वैचारिक रूप से राजद के खिलाफ है। लेकिन वह घर न बैठे या नाराज होकर दूसरी तरफ न जाए इसलिए ये योजनाएं चलाई गईं और अंत में इनका लाभ मिला।

परंतु ये तमाम योजनाएं पूरक की तरह थीं। असली खेल जाति की राजनीति का था। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव जाति गणना के बाद का पहला चुनाव था। जाति गणना में बिहार में जातियों की जो संख्या पता चली उसके बाद सारी जातियां अपनी संख्या के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी के लिए तैयार हो गईं। कह सकते हैं कि यह नीतीश कुमार की योजना का हिस्सा था, जो उन्होंने जातियों को इतना बिखरा दिया। चूंकि इन जातियों के पास पहले से नेता नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार उनके नेता हुए। इसका कारण यह है कि सामाजिक स्तर पर कमजोर और कम आबादी वाली पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का टकराव यादव के साथ है। सो, पिछले 20 साल से जिस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार राजनीति कर रहे थे उसी फॉर्मूले को उन्होंने आगे बढ़ाया।

तमाम गैर यादव पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ी जातियों को एकजुट किया और उसमें दलित व भाजपा के समर्थन से अगड़ी जातियों को जोड़ा। याद करें कैसे नीतीश कुमार 1994 में जब लालू प्रसाद से अलग हुए थे तब उन्होंने गैर यादव पिछड़ी जातियों में कोईरी, कुर्मी और धानुक की करीब 10 फीसदी आबादी का एक समीकरण बनाया था। आज तक यानी 30 साल बाद भी वह समीकरण काम कर रहा है। इसी तरह नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद से हर चुनाव में बिहार में बताया जाता है कि वे अति पिछड़ी जाति से आते हैं। सो, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर गैर यादव पिछड़ा व अति पिछड़ा को साथ रखना बहुत आसान हो गया।

दूसरी ओर समस्या यह है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने मुस्लिम और यादव यानी माई समीकरण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह लालू प्रसाद यादव के समय से ही शुरू हुई समस्या है। जब 1990 में वे मुख्यमंत्री बने तो वे गरीबों के मसीहा थे। उसके बाद 1995 में पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए तो पिछड़ों के नेता हुए और उसके बाद वे मुसलमानों और यादवों के नेता बन गए। तेजस्वी यादव लाख कोशिश करके भी इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने बार बार ए टू जेड का समीकरण बनाने की बात कही लेकिन यह एक सांस्थायिक प्रयास नहीं था। उनको लगता रहा कि वे चुनाव में टिकट दे देंगे तो जातियों का वोट उनको मिल जाएगा। इस उम्मीद में उन्होंने इस बार टिकटों में विविधता लाने का प्रयास किया। लेकिन जातियों को साधना इतना आसान नहीं होता है।

पारंपरिक नौकरियों पर आंच के बावजूद नये अवसर

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

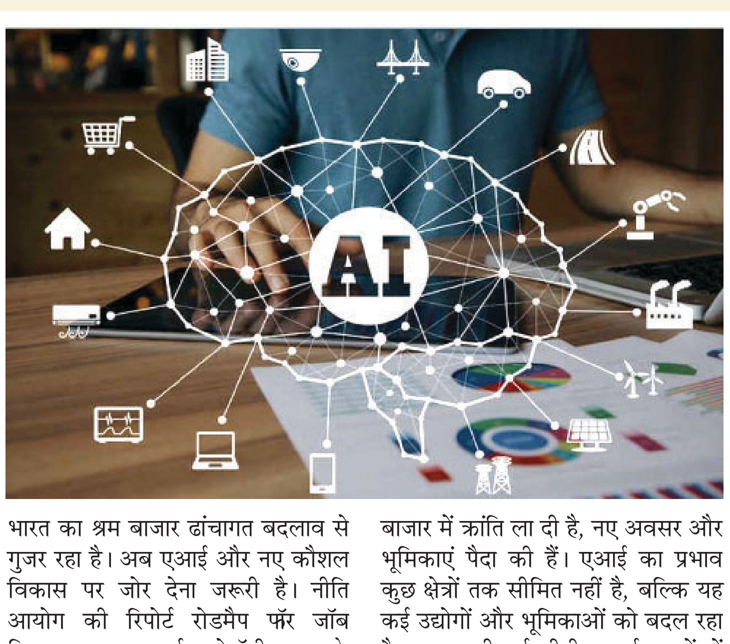

नीति आयोग की रिपोर्ट रोडमैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी 2025 के मुताबिक एआई के बढ़ते प्रभाव से जहां 2031 तक बड़ी संख्या में पारंपारिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, वहीं एआई से जुड़ी करीब 40 लाख नई नौकरियां निर्मित होते हुए दिखाई देंगी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नई पीढ़ी को प्रारंभिक स्तर से ही भविष्य की तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की सार्थक पहल की है। इसके मद्देनजर आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से देशभर के सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही एआई पढ़ाने का फैसला किया है। इन दिनों भारत में श्रमशक्ति और रोजगार बाजार, पर आई रिपोर्टों में दो बातें रेखांकित हो रही हैं। एक भारत की नई पीढ़ी के लिए उद्योग-कारोबार की नई जरूरतों और नई डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत एआई की नौकरियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। दो, विदेशों में भी भारत की एआई स्किल्स से सुसज्जित प्रतिभाओं के लिए मौके बढ़ रहे हैं।

हाल ही में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर, 2025 में एआई और मशीन लर्निंग दक्षता की नौकरियों में 61 फीसदी की वृद्धि हुई है। इनकी मांग आईटी व गैर आईटी क्षेत्र में भी बढ़ रही है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय, श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे के तहत स्वीकार किया है कि भारत का श्रम बाजार ढांचागत बदलाव से गुजर रहा है। अब एआई और नए कौशल विकास पर जोर देना जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट रोडमैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी 2025 के मुताबिक एआई के बढ़ते प्रभाव से जहां 2031 तक बड़ी संख्या में पारंपारिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, वहीं एआई से जुड़ी करीब 40 लाख नई नौकरियां निर्मित होते हुए दिखाई देंगी।

निस्संदेह इस समय एआई फोकस की वजह से कई कंपनियों में पारंपारिक नौकरियां खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण नौकरियां खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां सृजित होती हैं। वस्तुत: एआई के आगमन ने नौकरी बाजार में क्रांति ला दी है, नए अवसर और भूमिकाएं पैदा की हैं। एआई का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई उद्योगों और भूमिकाओं को बदल रहा है। भारत की नई पीढ़ी एआई कामों में लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम आल्ट मैन के मुताबिक एआई के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। गुगल के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक भारत की गणित में दक्ष नई पीढ़ी के लिए एआई में अपार संभावनाएं हैं।

इस समय भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक भारत में एआई का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जहां इस वर्ष 2025 में भारत का एआई बाजार 13.05 अरब डॉलर मूल्य की ऊंचाई पर है, वहीं यह बाजार आकार 2032 में 130.63 अरब डॉलर मूल्य का अनुमानित है। भारत में प्रौद्योगिकी और एआई पारिस्थितिकी तंत्र में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में 1,800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप हैं, और पिछले वर्ष शुरू किए गए नए स्टार्टअप में से लगभग 89 फीसदी ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। एआई अपनाने वाले अग्रणी क्षेत्रों में औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र शामिल हैं। ये एआई के कुल मूल्य में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

आज एआई को लेकर निवेश की वैश्विक होड़ लगी हुई है। हाल ही में 14 अक्तूबर को दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने विशाखापट्टनम में एक बड़ा डेटा सेंटर और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) हब बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी कंपनी अगले पांच साल में यानी 2030 तक भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। निस्संदेह, यह एआई हब भारत के डिजिटल भविष्य में एक माइलस्टोन है। वस्तुत: इस एआई हब से न केवल करीब दो लाख नए रोजगार मौके तैयार होंगे, बल्कि यह टेक इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।

एआई स्किल्स से प्रशिक्षित भारतीय युवाओं के लिए विदेशों में भी मौके बढ़ रहे हैं। दुनिया की जनसांख्यिकी भारत के पक्ष में खड़ी है। कई देशों में जन्म दर गिर चुकी है और वृद्ध जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 4.5 से 5 करोड़ श्रमिकों की कमी हो जाएगी। ऐसे में ‘ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्राम इंडिया फाउंडेशन’ का मानना है कि भारत को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी उच्च कौशल से प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार अब बड़े पैमाने पर श्रम बल को विदेशों में रोजगार दिलाने की दिशा में कदम उठा रही है। पिछले छह वर्षों में भारत 20 से अधिक देशों के साथ लेबर-मोबिलिटी समझौते कर चुका है।

इनमें यूरोप, एशिया और खाड़ी के विकसित देश भी हैं। भारतीय श्रमबल को वैध रास्ते से विदेशों में भेजा जा सके और उनकी सुरक्षित वापसी और पुनर्वास भी सुनिश्चित हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के विदेश मंत्रालय ने नौ अक्तूबर को ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2025 का मसौदा जारी किया है, ऐसे श्रम निर्यात माडल से भारत के एआई स्किल्स से दक्ष लाखों युवाओं को विदेशों में अच्छे रोजगार के मौके प्राप्त होंगे।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
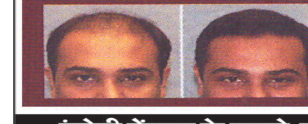

JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बैंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

93 उपार्जन केंद्र में 1322 किसानों ने धान बिक्री किये

दुर्ग। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 87 सहकारी समितियों अंतर्गत 102 धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की जाएगी। मंगलवार 18 नवम्बर 2025 को 93 उपार्जन केन्द्रों में 1322 किसानों से 6,897.16 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई। उपार्जन केंद्रों में धान की तोलाई, बोरे की सिलाई, स्टेग लगाने का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों में खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त कर दिए गए है। सी.सी.बी. के प्रभारी नोडल अधिकारी हृदेश शर्मा से मिली जानकारी अनुसार जिले में इस वर्ष 6,16,435 मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी के लिए जिले में 1,12,446 किसानों का पंजीयन किया गया है। धान विक्रय के लिए कुल रकबा 1,12,255 हेक्टेयर पंजीकृत है, इनमें 11827 हेक्टेयर एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हो पाया है। छूट प्राप्त वर्ग का रकबा 517 हेक्टेयर है। इसी तरह गत वर्ष धान विक्रय के लिए कुल पंजीकृत खसरे 4,36,399 थे। इस वर्ष पंजीकृत खसरों की संख्या 4,52,469 है। जिले में किसान प्राप्त टोकन तिथि के आधार पर अपने उत्पादित धान का विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं।

राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खेलो इंडिया लघु केन्द्र मर्रा, पाटन की बालिका का चयन

दुर्ग। 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सब-जूनियर (बालक/बालिका वर्ग) कबड्डी चैम्पियनशिप का आयोजन कबड्डी प्रशिक्षण केन्द्र पेण्ड्रा में 25 से 27 अक्टूबर 2025 तक सम्पन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में खेलो इंडिया लघु केन्द्र मर्रा, पाटन की प्रतिभाशाली बालिका कु. लक्ष्मी नेताम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दुर्ग जिला का प्रतिनिधित्व किया। खेल एवं युवा कल्याण से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के अंतर्गत ब्लॉक दुर्ग, पाटन एवं धमधा के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से कु. लक्ष्मी नेताम ने अपने उम्दा खेल कौशल से सभी का ध्यान आकर्षित किया। जिला प्रशासन एवं विभाग के अधिकारियों ने कु. लक्ष्मी नेताम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

चाकूबाजों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों का सम्मान, एसएसपी ने दिया सर्टिफिकेट

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। दुर्ग जिले में चाकूबाजी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए विगत माह जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्र के चाकूबाजों को चिन्हित कर कुल 22 चाकूबाजों को पकड़ा गया। इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर जेल दाखिल किया गया। इसी प्रकार बुलेट मोटर सायकल में मोडिफाइड साईलेंसर लगाकर तेज गति से चलाते हुए पटाखे की आवाज निकालने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इन प्रकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुल 28 पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने इन कर्मियों को प्रशस्ती पत्र देकर इनके काम की सराहना की।

सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों में 22 प्रधान आरक्षक व आरक्षक तथा 6 एएसआई शामिल हैं। यातायात विभाग के एएसआई स्तर के 6 पुलिस कर्मियों ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए बुलेट मोटर सायकल में मोडिफाइड साईलेंसर लगाकर चलाने वालों पर कार्रवाई की।

सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों में एएसआई रमेश दुबे यातायात, एएसआई विनोद सिंह यातायात, एएसआई अश्वनी सिंह यातायात, एएसआई प्रवीण सिंह यातायात, एएसआई नन्दू यादव यातायात, एएसआई राजू उर्वसा थाना सुपेला, आरक्षक कमलकांत अंगूरे दुर्ग, आरक्षक प्रशांत पाटनणकर, प्रधान आरक्षक ज्ञानदत्त मिश्रा, मोहन नगर, प्रधान आरक्षक दिनेश सोनी मोहन नगर, आरक्षक राजकिशोर तिवारी मोहन नगर, आरक्षक ऋतुराज सिंह मोहन नगर, आरक्षक गजेन्द्र साहू मोहन नगर, प्रधान आरक्ष रोहित कर्माकर पद्मनाभपुर, आरक्षक खिलेश कुर्रे पद्मनासपुर, प्रधान आरक्षक अमर सिंह सुपेला, आरक्षक सूर्य प्रताप सिंह सुपेला, आरक्षक अजीत सिंह सुपेला, आरक्षक दुर्गेश सिंह सुपेला, आरक्षक प्रीतम सिंह हरिवंश सुपेला, आरक्षक रजनीकांत वैशाली नगर, आरक्षक रवि साव वैशाली नगर, आरक्षक नियाज खान वैशाली नगर, आरक्षक दिनेश डहरिया भिलाई नगर, आरक्षक इसरार अहमद भिलाई नगर, आरक्षक छोटेलाल भिलाई नगर, आरक्षक भौखम साहू नंदिनी नगर और आरक्षक नीलमदास गोस्वामी नंदिनी नगर शामिल है।

मैत्री बाग में 40वां कब-बुलबुल उत्सव

बीएसपी ईएमएमएस-6 बना चैंपियन

बीएसपी की विभिन्न स्कूलों के लगभग 200 कब-बुलबुलों ने इस रंगारंग उत्सव में लिया भाग

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। बीएसपी के शिक्षा विभाग एवं भारत स्काउट गाइड जिला संघ भिलाई के तत्वावधान में 40वां कब-बुलबुल उत्सव मनाया गया। मैत्रीबाग में हुए उत्सव का उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मुख्य जिला आयुक्त भिलाई संघ एवं महाप्रबंधक (शिक्षा विभाग) शिखा दुबे द्वारा किया गया। 40वें कब-बुलबुल उत्सव में इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल सेक्टर-6 विजेता रही। इस अवसर पर जिला आयुक्त (गाइड) एवं प्राचार्या बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-10 सुमिता सरकार ने अपने स्वागत उद्बोधन में इस श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए सभी कब-बुलबुल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं तथा उत्सव में शामिल शालाओं एवं नन्हे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। बीएसपी की विभिन्न शालाओं के लगभग 200 कब-बुलबुलों ने इस रंगारंग उत्सव में भाग लिया। ध्वजारोहण एवं झंडा गीत के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में प्रार्थना के पश्चात् बच्चों ने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि शिखा दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि कब-बुलबुल गतिविधियाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा अनुशासन, जिम्मेदारी और नेतृत्व जैसे मूल्यों को बचपन से विकसित करती हैं।

विभिन्न विषयों पर बच्चों ने की चित्रकारी

चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रकृति संरक्षण, प्रदूषण जागरूकता, पशु-पक्षी सुरक्षा, बालिका शिक्षा और देशभक्ति जैसे सामाजिक विषयों को चित्रित किया। विविध वेशभूषा प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया। गंध पहचान, स्वाद पहचान, तथा गाँठ बाँधो प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी त्वरित पहचान क्षमता, एकाग्रता और कौशल का प्रदर्शन किया। साथ ही साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत कब विद्यार्थियों ने 12 फीट ऊँची रस्सी पर चढ़कर अपनी फुर्ती व साहस का परिचय दिया, वहीं बुलबुल छात्राओं ने 15 मीटर रस्से पर संतुलन दिखाते हुए अपने शौर्य एवं शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। सभी प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन शासकीय विद्यालयों में कार्यरत कब-बुलबुल विशेषज्ञ निर्णायकों द्वारा प्रस्तुतिकरण, समय, गणवेश एवं कौशल के मानदंडों के आधार पर किया गया।

सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि ने किया पुरस्कृत

समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार तथा विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक शिवराजन नायर थे। अतिथियों का स्वागत स्कार्फ पहनाकर किया गया तथा उन्होंने विभिन्न शालाओं द्वारा सुसज्जित बुलबुल-ट्री का अवलोकन किया। समापन समारोह में कब-बुलबुलों ने समूह नृत्य और विविध वेशभूषा की प्रस्तुति दी। इस अवसर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास, जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर मजबूत राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक (शिक्षा) मनीष तिवारी द्वारा किया गया व धन्यवाद ज्ञापन भिलाई विद्यालय सेक्टर-2 के प्राचार्य विजय सिंह पवार ने दिया।

भिलाई निगम क्षेत्र में सख्त कार्रवाई, अवैध होर्डिंग,सड़क बाधा पर जुर्माना

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई नगर। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के सख्त निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 04 नेहरू नगर क्षेत्र में विशेष चालानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सड़क पर बाधा उत्पन्न करने और अनाधिकृत रूप से अवैध होर्डिंग लगाने वाले विभिन्न व्यवसायी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई।

निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 9,000 की राशि का जुर्माना (चालान) वसूल किया। टाइटन आई प्लस 7,000 रुपए, इंग्लिश हब 500 रुपए, किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलर्स 1,500 रुपए इस तरह कुल चालानी कार्रवाई 9,000 रुपए जमा कराया गया।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। सभी व्यापारियों और नागरिकों से अपील की जाती है कि वे अपने व्यवसाय संचालन में सार्वजनिक सड़कों को बाधित न करें और निगम की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के होर्डिंग या विज्ञापन सामग्री का प्रदर्शन न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

धान खरीदी में डिजिटल क्रांति-'तुहर टोकन मोबाइल ऐप', घर बैठे टोकन सुविधा

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। धान खरीदी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और किसान-हितैषी बनाने के लिए 'तुहर टोकन मोबाइल ऐप' की शुरुआत की है। यह ऐप किसानों को अब घर बैठे ही धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उपार्जन केंद्रों में लगने वाली लंबी कतारों और भीड़ से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। किसान अपने मोबाइल नंबर और आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से इस ऐप में आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। किसान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप के माध्यम से अपने धान बेचने हेतु टोकन बुक कर सकेंगे। टोकन वितरण को किसानों की श्रेणी के अनुसार विभाजित किया है- सीमांत किसान अधिकतम 1 टोकन, लघु किसान अधिकतम 2 टोकन, दीर्घ किसान अधिकतम 3 टोकन। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों की प्रतिदिन की कुल खरीदी क्षमता का 70 प्रतिशत भाग ऐप के माध्यम से मिलने वाले टोकनों के लिए आरक्षित रहेगा। 80 प्रतिशत टोकन लघु और सीमांत किसानों, 20 प्रतिशत टोकन दीर्घ किसानों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इससे खरीदी केंद्रों में भीड़ प्रबंधन भी बेहतर होगा और छोटे किसानों को प्राथमिकता सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं में ड्रेस कोड होगा काला, नीला, हरे रंग के कपड़े पहनने पर बैन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 07 दिसम्बर 2025 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 02.15 बजे तक आयोजित होगी। जिले के 77 केन्द्रों में आयोजित इस परीक्षा में 28,235 अभ्यर्थी शमिल होंगे।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देशों के तहत परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यह परीक्षा प्रात:12 बजे से प्रारंभ होगा, मुख्य द्वार प्रात:11.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटविर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णत: वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन लेकर ही आयें।

नशा मुक्तभारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ : शपथ कार्यक्रम आयोजित

विभागों, कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं सहित स्कूल, उच्च शिक्षा व चिकित्सा संस्थानों में हुआ कार्यक्रम

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार 'नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 18 नवंबर को जिलेभर में व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के सभी विभागों, कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं सहित स्कूल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कृषि शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं, महिला समूहों, स्वयं सेवकों तथा आम नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली।

इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा स्व. सेठ रतनचंद सुराना कॉलेज के सहयोग से कॉलेज परिसर हॉल में विशेष नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित

छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अमृतसर, पंजाब में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक देखा।

इस अवसर पर महापौर अल्का बाघमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिले में चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया। अन्य अतिथियों ने भी नशा उन्मूलन हेतु समाज की सक्रिय भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ए.पी. गौतम, वार्ड पार्षद सरिता विनोद चन्द्राकर, पार्षद कुलेश्वरी ठाकुर, पार्षद ज्ञानेश्वर ताम्रकार, सुराना कॉलेज की प्राचार्य डॉ. पूजा मल्होत्रा, गायत्री परिवार के संयोजक पी.एल. साव एवं योगेन्द्र कुमार, कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र के संचालक अजय कल्याणी, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी के सदस्य बी.के. बेनीमाई साथ ही कॉलेज एवं विभाग के अन्य शिक्षक, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

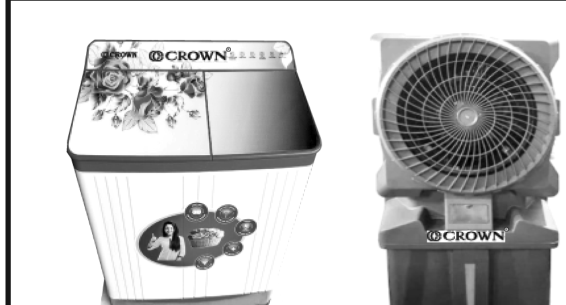

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

बस्तर ओलंपिक : स्थानीय युवाओं में नए युग का आगाज

रायपुर/बस्तर। बस्तर ओलंपिक के आयोजन से स्थानीय युवाओं में नए युग का आगाज हुआ, देशभर ने स्थानीय युवाओं की हुनर को देखा, यह सब विष्णुदेव साय की पहल से ही संभव हो पाया है। बस्तर के युवाओं में असाधारण प्रतिभा है। खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। विष्णुदेव सरकार का उद्देश्य है कि बस्तर के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को एक बेहतर मंच मिले और बस्तर ओलंपिक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। युवाओं में खेल भावना का विकास समाज को मजबूत बनाता है। स्वस्थ तन और स्वच्छ मन के लिए खेल अत्यंत आवश्यक हैं। यहां के खिलाड़ी जिस मेहनत और समर्पण के साथ खेल रहे हैं, वह आने वाले समय में उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। बस्तर ओलंपिक ने बस्तर के विकास की यशोगाथा और शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम किया। बस्तर ओलम्पिक के माध्यम से साय सरकार बस्तर अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा देने में सफल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन केवल खेल नहीं है, बल्कि बस्तर की संस्कृति, उत्साह, और प्रतिभा का उत्सव है। यह आयोजन एक संदेश देता है कि बस्तर का असली चेहरा इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि माओवाद की हिंसा। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं, तो यह एक सुखद संकेत है। बस्तर ओलम्पिक का सफल आयोजन लोगों में विश्वास दिलाता है कि बस्तर के युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए, तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई नही रोक सकता है। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा, बल्कि उन आत्मसमर्पित भाइयों और बहनों की प्रतिभा को भी देखा, जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है, वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है।

समर्थन मूल्य बढ़ने से खुश किसान, सुविधाजनक उपार्जन व्यवस्था से मिली राहत

कोरबा। जिले के ग्राम भैसमा निवासी किसान विनोद कुमार कंवर के लिए इस वर्ष की धान खरीदी कई मायनों में उम्मीद और संतोष लेकर आई है। पिछले साल उन्होंने 213 कट्टी धान उपार्जन केंद्र में बेचा था। वे बताते हैं कि इस बार भी मौसम की मेहरबानी से फसल उत्पादन लगभग उतना ही होने की संभावना है, जिसकी तैयारी उन्होंने फसल कटाई के तुरंत बाद मिंजाई शुरू करके कर दी है। किसान विनोद कुमार कहते हैं कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। उनके अनुसार, बढ़े हुए समर्थन मूल्य ने किसानों में नया उत्साह भरा है और इससे खेती-किसानी का भरोसा दोबारा मजबूत हुआ है। वे बताते हैं कि खरीदी के लिए अपना पंजीयन भी समय पर करवा लिया है। विनोद कुमार विशेष रूप से बताते हैं कि अब धान उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाएँ पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई हैं। पहले लंबी लाइनें लगती थीं, टोकन व्यवस्था नहीं होती थी और पूरा दिन इंतजार में बीत जाता था। लेकिन अब सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। उपार्जन केंद्र में सुव्यवस्थित टोकन व्यवस्था, त्वरित तौल, और किसानों को बिना परेशानी के अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध है। किसान विनोद कुमार का कहना है कि सरकार की इन पहलियों ने किसानों के लिए खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिससे वे समय और श्रम दोनों की बचत कर पा रहे हैं। बेहतर समर्थन मूल्य और सुविधाजनक व्यवस्था के कारण किसान वर्ग संतुष्ट है और आने वाले सीजन को लेकर उत्साहित भी है।

अनुराग सिंह देव ने 'आवास मेला 2025' के लोगो का किया अनावरण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के नागरिकों को आवासीय योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा राज्य स्तरीय 'आवास मेला 2025' का आयोजन 23, 24 और 25 नवंबर को रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में किया जा रहा है। इस मेले के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण आज गृह निर्माण मंडल मुख्यालय में मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव द्वारा किया गया।

इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण सहित मंडल के अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

लोगो अनावरण के बाद अध्यक्ष श्री सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'आवास मेला 2025' इसी दिशा में एक सार्थक पहल है, जहां मंडल की विभिन्न योजनाएँ और संपत्तियाँ एक ही मंच पर आम जनता के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।

अध्यक्ष सिंह देव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशभर में लगभग रु. 2000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पा रहा है।

आवास मेला 2025 में आगंतुकों के लिए कई सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु आवंटी पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। मेले में हितग्राही मात्र 1 प्रतिशत राशि जमा कर भवन बुक करा सकेंगे। रायपुर, नवा रायपुर एवं आसपास की परियोजनाओं के साइट विज़िट की विशेष व्यवस्था रहेगी, साथ ही घर खरीदने वालों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा लोन सुविधा भी दी जाएगी। निर्माण संबंधी जानकारी हेतु कई स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो का स्टॉल विशेष रूप से गुणवत्ता संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मेले में पंजीयन कराने वाले हितग्राहियों के लिए विशेष उपहार भी घोषित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2025 का किया भव्य अनावरण

प्रदेश में प्रतिष्ठित ट्रॉफी का आगमन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायीः मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से प्रतिष्ठित एफआईएच जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि विश्व की प्रतिष्ठित एफआईएच जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की चमचमाती ट्रॉफी पहली बार भारत टूर के तहत आज छत्तीसगढ़ पहुंची और विधानसभा परिसर में आयोजित गरिमामयी समारोह में इसका अनावरण किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि भारत में एफआईएच जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होना अत्यंत गर्व की बात है और इस ट्रॉफी का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए विशेष सम्मान का अवसर है। उन्होंने हॉकी इंडिया के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ट्रॉफी टूर देशभर में खेलों के प्रति उत्साह एवं प्रेरणा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा इस अभियान का शुभारंभ देश में खेल भावना को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शुरू से ही हॉकी की उर्वर भूमि रहा है। राजनांदगांव, बस्तर, जशपुर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जैसे जिलों से बड़ी संख्या में बच्चे हॉकी खेल में अपना भविष्य संवार रहे हैं। ट्रॉफी का यहां आगमन राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना के विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री साय ने कहा कि यह ट्रॉफी दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और सपनों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हॉकी इंडिया, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और छत्तीसगढ़ हॉकी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ट्रॉफी के भव्य अनावरण के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और छत्तीसगढ़ हॉकी के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, संघ के अन्य पदाधिकारी, हॉकी संगठन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

भारत पहली बार बनेगा जूनियर वर्ल्ड कप का मेजबान

गौरतलब है कि एफआईएच हॉकी जूनियर मेन्स वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। प्रतियोगिता 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी और तमिलनाडु के चेन्नई व मदुरै में आयोजित की जाएगी।

बोर्ड परीक्षा मे बेहतर परिणाम लाने करें सामूहिक प्रयास - सचिव परदेशी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि उन्हें एक आदर्श नागरिक भी बनाते हैं। शिक्षक उत्कृष्ट आचरण और उच्च नैतिकता का उदाहरण पेश करें। उन्होने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा लेकिन लापरवाही और अनैतिक गतिविधि में शामिल होने पर कार्यवाही भी होगी।

श्री परदेशी कल बलौदाबाजार जिला प्रवास के दौरान जिला ऑडिटोरियम में प्रचार्यो की बैठक लेकर बोर्ड परीक्षा तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने विगत वर्ष की परीक्षा परिणाम में 10 प्रतिशत की वृद्धि को बरकरार रखने सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिये।

श्री परदेशी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में बच्चों को पिछले प्रश्न पत्र एवं प्रश्न बैंक से उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कराएं।

श्री परदेशी ने अपार आईडी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी बच्चों के अपार आईडी बनाने का कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये। स्कूल शिक्षा सचिव ने हाल ही में सम्पन्न त्रैमासिक परीक्षा, अपार आई.डी. की प्रगति, यू-डाईप्लस 2025-26 प्रविष्टि, छात्रवृत्ति, मूलभूत सुविधा आदि एजेंडों पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने माध्यन्ह भोजन की गुणवत्ता हेतु नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये।

बैठक मे सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे, सहायक संचालक एवं प्राचार्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कुडो 6वें फेडरेशन कप में छत्तीसगढ़ के अव्यय शर्मा ने जीता कांस्य पदक

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित कुडो 6वें फेडरेशन कप टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के उभरते खिलाड़ी अव्यय शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। अव्यय शर्मा की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ कुडो एसोसिएशन ने उन्हें शुभकामनाएँ दीं। संघ के अध्यक्ष राजा कौशल, चेयरमैन अनुराधा सिंह, हेड कोच लिलीमा सोनी, तथा कोच भूपत सिंपई, मनीष सिंपई और परमेश्वर सिंपई ने अव्यय को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अव्यय की इस सफलता से पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है और खेल प्रेमियों ने भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है।

लक्ष्य तय करें, कठिनाइयों को अवसर में बदलें: राजेश अग्रवाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने रयान इंटरनेशनल स्कूल, रायपुर के बच्चों से आत्मीय मुलाकात की। यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भर नहीं रही, बल्कि जीवन मूल्य, लक्ष्य निर्धारण, संघर्ष, शिक्षा के महत्व और छत्तीसगढ़ के पर्यटन पर गहन और प्रेरक संवाद का अवसर बन गई। बच्चों ने बड़े ध्यान से मंत्री जी की बातों को सुना और इसे अपने स्कूली व आगामी जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख बताया।

मंत्री अग्रवाल ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ''हर छात्र को अपने अंदर स्वच्छता, संस्कार और अनुशासन का बीज बोना चाहिए। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उतनी जल्दी आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। कठिनाइयाँ हर जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें छिपे अवसर को पहचानना ही असली सफलता है। शिक्षा केवल अंकों के लिए नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और मजबूत व्यक्तित्व के निर्माण के लिए होती है।'' संवाद के दौरान एक छात्र ने मंत्री अग्रवाल से पूछा कि उन्हें राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। इस पर श्री अग्रवाल ने कहा, ''मुझे राजनीति में आने की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। बचपन से ही उन्हें लोगों की मदद करते, समाज के लिए काम करते देखता था। वहीं से मन में भावना आई कि जीवन ऐसा हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। राजनीति मेरे लिए सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम है।''

एक अन्य छात्र ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएँ हैं। इस पर अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि ''छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपात, गुफाएँ, पुरातात्विक धरोहरें, आदिवासी संस्कृति और लोक कला की अनूठी विरासत है। हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान मिले। इस क्षेत्र में हम उत्कृष्ट कार्य करेंगे, ताकि आप जैसी नई पीढ़ी अपने राज्य पर गर्व महसूस कर सके।''

स्कूली छात्रों ने मंत्री श्री अग्रवाल से आटोग्राफ लिया व उनके साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाई। मंत्री से मुलाकात पर स्कूली बच्चों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमे मंत्री जी से बात कर बहुत अच्छा लगा व उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, अब हम अपना लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही ईमानदारी से करेंगे। पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए भी ज़रूरी है। पहली बार किसी मंत्री से इतने करीब बैठकर बातचीत करने का मौका मिला है।

रयान इंटरनेशनल स्कूल के इन बच्चों और पर्यटन मंत्री के बीच हुआ यह संवाद सकारात्मकता, प्रेरणा और आत्मविश्वास से भरा रहा। यह मुलाकात बच्चों के लिए केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और भविष्य की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण सीख साबित हुई।

शिक्षा, लक्ष्य और आत्मविश्वास पर जोर

श्री अग्रवाल ने बच्चों को समझाया कि ''पढ़ाई का महत्व केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा कि हर विषय को ध्यान से पढ़िए, केवल रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। सवाल पूछने से कभी संकोच मत कीजिए। यही आदत आगे चलकर आपको अलग पहचान दिलाएगी। कठिन समय में घबराने के बजाय समाधान खोजिए, तब आप हर चुनौती को अवसर में बदल पाएँगे।''

3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ, केल्हारी के किसान त्रिभुवन की जिंदगी में लौटी खुशहाली

श्रीकंचनपथ समाचार

एमसीबी। खरीफविपणन वर्ष 2025-26 जिले के किसानों के लिए उम्मीदों और खुशियों का नया संदेश लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई किसान हितैषी नीतियों, प्रति एकड़ 21 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3100 रुपये की समर्थन मूल्य दर ने किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

इन्हीं लाभों का प्रत्यक्ष असर केल्हारी निवासी किसान त्रिभुवन नारायण सिंह पर देखने को मिला, जिनकी मेहनत और सरकारी व्यवस्थाओं के बेहतर क्रियान्वयन ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है।

त्रिभुवन नारायण सिंह इस वर्ष केल्हारी उपार्जन केंद्र में 99.60 क्विंटल धान बेचकर लगभग 3,08,760 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। वे बताते हैं कि खरीदी केंद्र में इस वर्ष व्यवस्था और भी बेहतर है तौल-कांटा, बारदाना, पानी एवं अन्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 90.60 क्विंटल धान बेचा था, और उस दौरान भी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम रही थी।

त्रिभुवन बताते हैं कि पिछले वर्ष मिली आय से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतों और रबी फसल की तैयारी की थी। इस वर्ष 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर ने उनकी उम्मीदों को और मजबूत किया है। उनका कहना है कि समय पर तौल, सरल प्रक्रिया और मंडी में उपलब्ध साफ-सुथरी सुविधाओं ने खेती को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया है।

त्रिभुवन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए जा रहे निर्णयों से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। किसान मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा यह बात अब जमीनी स्तर पर सच होती दिखाई दे रही है।

त्रिभुवन की तरह जिले के अन्य किसानों ने भी इस वर्ष की खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हित में बताया है। हर किसान की कहानी प्रदेश की समृद्धि का प्रतीक बन रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर कृषि राज्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती के आवेदन

कोरबा। एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली में आंगनबाड़ी कार्यकता एवं सहायिका भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र मसान 01 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रिक्त पद की पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं से 04 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

बिना स्क्रिप्ट पढ़े राशि खन्ना ने साइन की पवन की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह'

अभिनेत्री राशि खन्ना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म '120 बहादुर' को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं लेकिन कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, जिसकी स्क्रिप्ट पढ़े बिना उन्होंने साइन किया हो। हालांकि उन्होंने बताया कि तेलुगु फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' की स्क्रिप्ट सुने बिना ही इसे साइन किया।

एचटी को दिए एक इंटरव्यू में राशि खन्ना ने फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' के बारे में कई बातें बताई हैं। उन्होंने अपने सह-कलाकार पवन कल्याण की भी तारीफ की है। अपनी अगली फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में काम करने के बारे में पूछे जाने पर, राशि ने बताया 'यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे मैंने बिना स्क्रिप्ट सुने साइन कर लिया। मैंने हां कह दिया क्योंकि यह पवन कल्याण की फिल्म है। मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी क्योंकि उनके पास स्टारडम है। मुझे पता है कि यह उनकी फिल्म है और मैं इसका हिस्सा हूं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी आप ऐसी फिल्में मशहूर होने के लिए करते हैं।'

इसलिए पवन कल्याण को पसंद करती हैं राशि

पवन कल्याण के बारे में बात करते हुए राशि ने कहा 'मैं इस चीज को बहुत पसंद करती हूं कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं। दूसरी बात यह है कि आम लोगों को भी वह बहुत प्रेम करते हैं। इन सबके अलावा वह एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।' राशि ने आगे बताया 'उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है। मैंने सेट पर ऐसी छोटी-छोटी चीजें देखीं, जिनसे मैं हैरान हो गई। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है कि वो कितने अच्छे हैं। ये पहली बार था जब मैं किसी सेट पर किसी स्टार से इतना प्रभावित हुई।'

राशि खन्ना का वर्कफ्रंट

आपको बता दें कि राशि खन्ना अपकमिंग तेलुगु फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ नजर आने वाली हैं। वह 21 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर के साथ नजर आने वाली हैं। वह वेब सीरीज 'तलाखों में एक' में पुलिस का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं।

प्रेग्नेंसी रूमर्स पर भड़कीं टीवी एक्ट्रेस सायंतनी पोस्ट लिख बोलीं- ये क्या बकवास है? मैं प्रेग्नेंट नहीं

टीवी एक्ट्रेस सायंतनी घोष अपनी प्रेग्नेंसी रूमर्स की वजह से सुर्खियों में हैं। अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन अफवाहों पर बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चल रही खबरों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही अपने पोस्ट में बॉडी शेमिंग करने वालों को खूब खरी-खोटी भी सुनाई है।

सायंतनी मेरी बॉडी, मेरी लाइफ मेरी च्वाइस कैप्शन के साथ लिखती हैं- 'मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं मां बनने वाली हूं? लोगों के ऐसे सोचने के पीछे की वजह जानकर मैं हैरान रह गई। क्योंकि आजकल मैं ढीले कपड़े पहन रही हूं तो लोगों को लगता है, मैं प्रेग्नेंट हूं।

यह क्या बकवास है? दुर्भाग्य से हम इसे ही मॉर्डन और आगे सोच वाली समाज कहते हैं। लोग अब भी कितनी पुरानी सोच रखते हैं। वीमेन इम्पॉवरमेंट के नाम पर इतना शोर मचाया जाता है लेकिन महिलाओं को जज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्या विडंबना है ये?'

इसी पोस्ट में सायंतनी ये भी बताती हैं कि उन्हें ढीले कपड़े पहनना क्यों पसंद है। वो लिखती हैं- 'मैं 41 साल की मैरिड महिला हूं और प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूं क्योंकि मुझे यही पसंद है। उम्र के साथ, मेरा शरीर भी बदल गया है। अब यह एक खास तरह का हो गया है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अपने 20 और 30 के दशक में एक खास तरह की दिखती थी और अब मैं जैसी हूं वैसी ही हूं।

मैं तब भी इसकी मालिक थी, अब भी हूं। मैं तब भी कॉन्फिडेंट थी, अब भी हूं! जैसा कि कहते हैं, बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा स्थायी तत्व है।' अपने इस पोस्ट में सायंतनी ने लोगों से दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करने की रिक्वेस्ट की है। सायंतनी की वर्कफ्रंट की बात करें तो वो महाभारत, नागिन, नामकरण, कुमकुम एक प्यार सा बंधन, इतना करो ना मुझे प्यार जैसे शो का हिस्सा रही हैं। फिलहाल वो जी टीवी के शो जगधात्री का हिस्सा हैं।

धनुष के मैनेजर पर तमिल एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप बोलीं- काम देने के बहाने कास्टिंग काउच की कोशिश

तमिल टीवी एक्ट्रेस मान्या आनंद ने दावा किया है कि श्रेयस नाम के एक शख्स ने उनके साथ कास्टिंग काउच की कोशिश की, जो खुद को साउथ सुपरस्टार धनुष का मैनेजर बताता है। मान्या ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि श्रेयस लंबे समय से उनके साथ एडजस्टमेंट को लेकर बात कर रहा था। साथ ही काम दिलाने के नाम पर गलत तरीके की डिमांड कर रहा था।

तमिल वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने डिटेल में बताया कि कैसे श्रेयस ने उनसे और बाकी आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया और उन्हें धनुष से जुड़ी एक नई फिल्म प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया। इस दौरान उनसे श्रेयस ने ऐसी डिमांड की, जो उन्हें आपत्तिजनक लगे। मान्या याद करते हुए बताती हैं कि श्रेयस उनसे कहा कि ये एक एडजस्टमेंट और कमिटमेंट हैं। इस पर उन्होंने पूछा- 'कैसी कमिटमेंट? मुझे क्यों कमिटमेंट देनी होगी?' मान्या बताती हैं कि मैंने उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं इस तरह के किसी भी ऑफर में शामिल नहीं होना चाहती हैं लेकिन श्रेयस मुझे मजबूर करता रहा। श्रेयस ने मुझसे कहा- 'आप धनुष सर के होते हुए भी नहीं मानेंगी?'

इतना ही नहीं, मान्या ने यह भी दावा किया कि श्रेयस ने उन्हें धनुष के प्रोडक्शन हाउस, वंडरबार फिल्म्स के लोकेशन की जानकारी भी भेजी और मिलने के लिए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट भी भेजी थी, जिसे उन्होंने नहीं पढ़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मान्या ने कहा- 'मैंने इसे नहीं पढ़ा। मैं यह फिल्म नहीं कर रही हूं। हम कलाकार हैं। हम कुछ और काम कर रहे हैं। आप हमसे काम तो लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ और की उम्मीद नहीं करते।अगर हम आपकी डिमांड मान लेते, तो हमारा नाम कुछ और होता। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि लोग इस चलन को पहचानें और इसे सुलझाएं।' फिलहाल धनुष या उनके मैनेजर श्रेयस का इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया है। वहीं, धनुष जल्द ही डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने जा रही है।

फिल्म 'धुरंधर' में आर माधवन ने अपने लुक को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- पूरी मूवी में मैंने अपने होंठ पतले किए

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर आखिरकार आज मंगलवार को रिलीज हो गया। इस ट्रेलर रिलीज इवेंट के दौरान अभिनेता आर माधवन ने अपने किरदार के लुक के बारे में बताया। पढ़िए उन्होंने क्या कहा।

फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर आर माधवन ने अपने लुक पर बात की। उन्होंने कहा, 'मैं इस किरदार के लिए लुक टेस्ट कर रहा था, हमें सब कुछ सही करने में लगभग तीन से चार घंटे लगे। जब मैं अपने आपको देख रहा था, लग रहा था कि एक चीज मिसिंग है। तभी आदित्य धर आके बोलते हैं कि मैडी, अपने होंठ पतले करो तो पूरी फिल्म मैंने होंठ पतले करके ही किया है।'

आर माधवन ने आगे बातचीत में फिल्म को लेकर बताया कि जब आदित्य धर उनसे मिलने आए, तो वो उनकी रिसर्च और बातें सुनकर दंग रह गए थे। उन्होंने कहा- 'मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं कई ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये फिल्म होने वाली है। यह फिल्म जब रिलीज होगी, तो इंडियन सिनेमा में एक जॉनर की फिल्में बनना बंद हो जाएंगी।'

फिल्म 'धुरंधर' की बात करें तो आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं।

दीपिका पादुकोण को अपने फैसलों पर होता है पछतावा! अब फिल्म चुनते वक्त इन बातों का रखती हैं ध्यान

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में शामिल हैं। अपने 18 साल के करियर में दीपिका पादुकोण ने अब तक कई कामयाब फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'ओम शांति ओम' से की और वह पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 ए.डी.' में नजर आईं। हालांकि, उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकीं। हाल ही में दीपिका ने एक इंटरव्यू में माना कि कई बार उन्होंने गलत फैसले भी लिए हैं, जिसका उन्हें पछतावा है।

हार्पर्स बाजार इंडिया के साथ बातचीत में दीपिका ने बताया कि वह फिल्म चुनते वक्त किन बातों का ध्यान देती हैं। दीपिका ने बताया 'सबसे बड़ी चीज प्रमाणिकता है। जो भी चीज सच्ची नहीं लगती, वह मुझे रास नहीं आती। कभी-कभी लोग बहुत सारा पैसा देते हैं और सोचते हैं कि इससे सब कुछ हो जाएगा लेकिन वह काफी नहीं होता। मुझे लोगों या संदेश पर यकीन है और मैं उस पर कायम रहूंगी।

फैसलों पर विचार करती हैं दीपिका

दीपिका ने माना कि वह अपने विचार को लेकर इतनी स्पष्ट नहीं थीं। उन्होंने कहा 'क्या मैं हमेशा से चीजों को लेकर इतनी स्पष्ट थी? शायद नहीं। हालांकि अब मैं उस स्पष्टता तक पहुंच गई हूं। क्या मैं कभी-कभी पीछे मुड़कर सोचती हूं कि मैं क्या सोच रही थी? जी हां मैं सोचती हूं। इससे मैं सीखती हूं। शायद आज से 10 साल बाद, मैं आज के कुछ फैसलों पर सवाल उठाऊंगी जो फैसले अभी मुझे सही लगते हैं।'

पाइपलाइन में दो फिल्में

दीपिका की फिलहाल दो फिल्में पाइपलाइन में हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' में वह एक सहायक भूमिका में हैं। इसमें सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी जैसे कलाकार होंगे। यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है। इसके बाद दीपिका एटली के साथ अल्लू अर्जुन अभिनीत फिल्म एए22×ए6' में काम कर रही हैं। यह 2027 में रिलीज होगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया राज्य जीएसटी विभाग के नये कार्यालय का शुभारंभ, कहा-

मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत व्यापार और सहयोगी कर प्रशासन अनिवार्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग के 5वें एवं 6वें तल पर निर्मित आयुक्त, राज्य कर के नए अत्याधुनिक कार्यालय भवन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त सचिव मुकेश बंसल, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन सतीश थौरानी एवं प्रतिनिधिगण, CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, CA एसोसिएशन व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित रायपुर मुख्यालय एवं विभिन्न संभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है, जब व्यापार तरक्की करे और व्यापारियों को सरल एवं सहयोगी कर प्रशासन मिले। राज्य सरकार जनकल्याण के कार्यों को प्रभावी ढंग से तभी आगे बढ़ा सकती है, जब राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ हो। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि GST विभाग के अधिकारी व्यापारियों की समस्याओं को समर्पण भाव से दूर करें, तकनीकी कठिनाइयों में उनकी सहायता करें और उन्हें नियमों व प्रक्रियाओं को समझने में सहयोग प्रदान करें। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि त्रस्ज्ञ 2.0 कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों पर कर का बोझ कम करना, खपत को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और छोटे व्यवसायों व किसानों को मजबूती देना है।

उन्होंने बताया कि इन सुधारों से औसत भारतीय परिवार को सालाना 25 हजार से 40 हजार तक की सीधी बचत मिलेगी, वहीं किसानों, छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की आय में 10-20 प्रतिशत वृद्धि संभव होगी।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनयापन संबंधी वस्तुओं पर कर घटने से परिवारों पर व्यय का बोझ कम होगा और जीवन अधिक सुरक्षित व सुलभ बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीएसटी 2.0 से मिलने वाली राहत का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, यह विभाग की जिम्मेदारी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से लागू त्रस्ज्ञ 2.0 ने कर संरचना को सरल बनाया है और कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुधारों का लाभ व्यापारियों, मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों, विद्यार्थियों और आम उपभोक्ताओं तक बिना किसी बाधा पहुँचाया जाए।

उत्कृष्ट करदाताओं को किया सम्मानित

कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 के उत्कृष्ट करदाताओं को उच्च कर भुगतान, उत्कृष्ट अनुपालन और निरंतर वृद्धि के लिए Ta&payer Appreciation Award प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वाले प्रमुख संस्थानों में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमपीसीजी मोबाइल प्रा. लि., एनटीपीसी, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, सारडा एंड मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफरेलवे, भिलाई स्टील प्लांट और एबिस फूड्स एंड प्रोटीन प्रा. लि. शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सम्मान राज्य के अनुकरणीय करदाताओं को प्रोत्साहित करने तथा कर अनुपालन को मजबूत करने का कदम है।

आधुनिक, पारदर्शी व करदाता हितैषी प्रशासन की दिशा में कदम

अपने संबोधन के अंत में वित्त मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में निर्मित नया कार्यालय भवन राज्य कर विभाग की पारदर्शिता, कार्यकुशलता और करदाता हितैषी सेवाओं को नई दिशा देगा। यह भवन आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था और सहज कर सेवा प्रणाली का नया प्रतीक है।

ग्रामीण प्रतिभा का हुआ सम्मान, विकासखंड स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। विकासखंड स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का समापन आज बलौदाबाजार स्पोर्ट्स स्टेडियम में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा तथा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और सभी खिलाड़ियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई।

अपने उद्बोधन में मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि खेल जीवन के हर उतार-चढ़ाव का सामना करना सिखाते हैं। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में छिपी प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी एक साथ जुटे हैं, जो खेल जगत के लिए उत्साहजनक है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीत-हार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना है। उन्होंने कहा कि खेलकूद से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, साथ ही टीम स्पिरिट, अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मिशन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव की महत्ता बताते हुए कहा कि इससे युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। सांसद अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न शासकीय सेवाओं में नियुक्त कर रही है और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कई खिलाड़ी आज सरकारी पदों पर कार्यरत हैं।

उल्लेखनीय है कि सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 21 सितंबर से 13 विधाओं में पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। 9ङ्क19 वर्ष एवं 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने खो-खो, कुश्ती, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, तैराकी, शरीर सौष्ठव, शतरंज, फुगड़ी, कबड्डी, गेड़ी दौड़, रस्सा-कस्सी और रस्सीकूद सहित अन्य खेलों में दमखम दिखाया। विजेता खिलाड़ी अब जिला एवं राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और नागरिक उपस्थित रहे।

लखनपुर ब्लॉक के कुन्नी में विकास कार्यों की सौगात, ग्रामीणों में खुशी की लहर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुन्नी में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने करोड़ों रुपये के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्नी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, 10 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से पोड़ी से जगन्नाथपुर मार्ग पर रिहंद नदी पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य, 8 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से लिपिंगी से मुड़ापारा मार्ग पर रिहंद नदी पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग, 26 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से अमगसी से कुन्नी 13 किमी लंबे मार्ग का मजबूतीकरण व चौड़ीकरण, 30 लाख रूपए लागत से महतारी सदन का निर्माण कार्य तथा 56 लाख रूपए की लागत से हाट-बाजार का निर्माण कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुन्नी और आसपास के क्षेत्रों के लिए इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों की मंजूरी पहली बार मिली है। यह यहां के लोगों के लिए वरदान है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल का भी धन्यवाद किया और बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन होने से स्टाफ भी 16 से बढ़कर 40 होगा, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। मंत्री श्री अग्रवाल ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सदैव आप सबके सुख-दुख में आपके साथ रहूंगा। क्षेत्र के लोग अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, यह विष्णुदेव साय सरकार की देन है। करोड़ों के निर्माण कार्यों के भूमिपूजन ने ग्राम पंचायत कुन्नी व पूरे क्षेत्र को विकास की नई दिशा दी है। ग्रामीणों ने इसे सपनों का साकार होना बताते हुए पर्यटन मंत्री अग्रवाल व साय सरकार के प्रति आभार जताया।

समग्र शासन दृष्टिकोण के साथ दिव्यांगजन राज्य नीति पर हुआ मंथन

एक अभेद्य और समावेशी नीति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदमः समाज कल्याण सचिव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए एक मज़बूत और व्यापक नीति तैयार करने के उद्देश्य से, समाज कल्याण विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से आज रायपुर के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में एक दिवसीय 'राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया। यह आयोजन राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक सुरक्षित और अधिकार-आधारित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत में समाज कल्याण विभाग के सचिव, भुवनेश यादव ने प्रस्तावित राज्य नीति और कार्ययोजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिए एक समर्पित राज्य नीति की आवश्यकता है, जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हो।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष, लोकेश कावड़िया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए नीति में ठोस प्रावधानों की वकालत की। इस महत्वपूर्ण विमर्श में समाज कल्याण विभाग की संचालक, श्रीमती रोकतिमा यादव, यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री चेतना देसाई और सुश्री शिखा राणा ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न विभागों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पुलिस, आदि) के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर नीति निर्माण में अपना योगदान दिया। नीति को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आयोजित 'एक्सपर्ट सेशन' में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

9 थीमेटिक समूहों में मंथन: 'समग्र शासन दृष्टिकोण'

ड्राफ्ट नीति की गहन समीक्षा के लिए प्रतिभागियों को 9 थीमेटिक समूहों में विभाजित किया गया। ये समूह किसी एक विभाग तक सीमित न रहकर विभिन्न विभागों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुलभता आदि) के कार्यक्षेत्रों पर आधारित थे। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में 'समग्र शासन दृष्टिकोण' को बढ़ावा देना था, ताकि दिव्यांगता का विषय केवल समाज कल्याण विभाग तक सीमित न रहे बल्कि सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी बने।

प्रत्येक समूह ने ड्राफ्ट नीति का बारीकी से निरीक्षण किया और इसे बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। यह चर्चा राज्य के लिए एक मज़बूत और अभेद्य नीति बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होगा; विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ यह विचार-विमर्श आगे भी जारी रहेगा ताकि अंतिम नीति में कोई भी कमी न रहे और यह हर दिव्यांगजन को पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान कर सके।

नशामुक्ति अभियान की शपथ

कार्यक्रम के समापन सत्र में, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के संकल्प के साथ सभी उपस्थित अधिकारियों, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने 'नशामुक्ति अभियान' के तहत नशा न करने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ ली।

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत जिले के बच्चों ने किया शैक्षणिक भ्रमण

श्रीकंचनपथ न्यूज

बलरामपुर। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन और जिला शिक्षा अधिकारी एम. आर. यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत एक विशेष शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण कार्यक्रम में सभी विकासखण्डों से चयनित 100 बालक-बालिकाओं ने सरगुजा संभाग के प्रमुख शैक्षणिक एवं औद्योगिक संस्थानों का अवलोकन किया।

भ्रमण के दौरान छात्रों ने सरगुजा कृषि विज्ञान केन्द्र, शक्कर कारखाना, राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय (अजिरमा) तथा दरिमा हवाई पट्टी (अम्बिकापुर) का दौरा किया। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर मिला। इस दौरान विशेषज्ञों ने बच्चों को आधुनिक तकनीकों, उद्योगों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। विद्यार्थियों ने विविध प्रयोगों, मशीनों, शोध कार्यों को करीब से देखा और समझा।भ्रमण के दौरान बच्चों में उत्साह देखने को मिला। जिला शिक्षा अधिकारी एम. आर. यादव ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों में विज्ञान एवं नवाचार के प्रति रुचि बढ़ेगी। आगे भी समय समय पर ऐसे शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे।

जनजातीय स्वाभिमान का उजास

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गूँजा इतिहास और गौरव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत - ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संभागायुक्त महादेव कांवरे ने की।

कुलपति कांवरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिरसा मुंडा आधुनिक भारत का वह सपना देखते थे जिसमें विकास और शिक्षा जन-जन तक पहुँचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित जन-मन योजना एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ये योजनाएँ जनजातीय अंचलों में विकास की नई राह बना रही हैं।

मुख्य अतिथि विकास मरकाम ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास को याद करने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि केवल 14 वर्ष की अल्प आयु में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका और जलङ्कजंगलङ्कजमीन की रक्षा का नेतृत्व किया। उन्होंने परलकोट आंदोलन के गेंदसिंह, वीर नारायण सिंह, गुंडाधूर और लांगुर किसान जैसे जनजातीय नायकों के योगदान को भी स्मरण किया। श्री मरकाम ने युवाओं से आह्वान किया कि शिक्षा लो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने त्योहार और अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने कार्यक्रम की प्रासंगिकता और बिरसा मुंडा जयंती के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला

छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को जीवंत बना दिया। रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

एमबीए (एचए) विभाग द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों व कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मेडिकल कैंप में डॉ. देवेंद्र कश्यप एवं उनकी टीम की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम संयोजक डॉ. आशुतोष मंडावी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं और विद्यार्थियों को जनजातीय समाज पर शोध के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

कार्यक्रम में उप कुलसचिव सौरभ शर्मा, विभागाध्यक्षगण, अग्रसेन महाविद्यालय की शिक्षिका ऋतुलता तारक एवं ईशा गोस्वामी सहित अनेक अतिथि, शोधार्थी व छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

कृषि विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्रीय अन्तर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रायपुर में पूर्वी क्षेत्रीय अन्तर्महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 की शुरूआत कल 19 नवम्बर से होगी। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल प्रात: 10 बजे कृषि महाविद्यालय परिसर में पूर्वी क्षेत्रीय अन्तर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय अन्तर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय रायपुर, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, कृषि महाविद्यालय, महासमुंद, कृषि महाविद्यालय भाटापारा, कृषि महाविद्यालय, मर्रा, (पाटन) तथा कृषि महाविद्यालय, गरियाबंद के लगभग 300 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। 19 से 21 नवम्बर, 2025 तक आयोजित होने वाली इस तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अन्तरमहाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धाओं में लम्बी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, हर्डल दौड़ तथा 4ग्100 मीटर एवं 4ग्400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक स्पर्धाओं के अंतर्गत वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संचालित समस्त कृषि महाविद्यालयों को चार जोन में विभाजित किया गया, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत 11 महाविद्यालय आते हैं। विश्वविद्यालय के पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण जोन के 28 महाविद्यालयों में भी अन्तरमहाविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। समस्त कृषि महाविद्यालयों के चार जोन में आयोजित होने वाली अन्तरमहाविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता से प्रत्येक जोन के चयनित 40-40 विद्यार्थियों की एक टीम गठित की जाएगी।

खास खबर

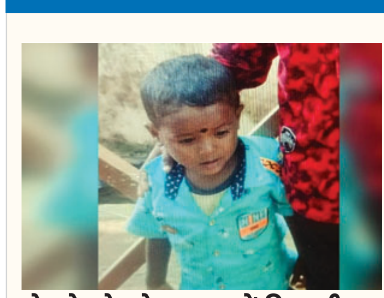

खेलते-खेलते तालाब में गिरा तीन साल का मासूम, डूबने से हुई मौत

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र के गोढा गांव में मंगलवार शाम एक मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, तीन साल का शिवांश उरांव घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक पास ही स्थित तालाब की ओर पहुंच गया। परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ देर बाद गांव के ही एक युवक मुनेम इक्का ने तालाब के किनारे बच्चे को पानी में डूबा देखा और तुरंत परिजनों को मामले की सूचना दी। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे नजदीकी अस्पताल कोटमी पहुचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए परिजनों को पेंड्रा के शासकीय अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।। वहीं मासूम की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

व्यापारी के गोदाम में मिला अवैध धान मंडी विभाग ने 50 कट्टा जब्त किया

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। खरसिया में पंजीकृत एक व्यापारी के गोदाम में जांच के दौरान 50 कट्टा अवैध धान पाया गया, जिसे मंडी विभाग ने जब्त कर लिया है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, प्रशासन के निर्देश पर जिले में पंजीकृत व्यापारियों के गोदामों और प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। मंगलवार दोपहर मंडी सचिव प्रशांत कुलमित्रा और मंडी उपनिरीक्षक की टीम ने ग्राम डोमनारा निवासी भभीक्षण साव की किराना दुकान में जांच की। दुकान के बाद टीम ने उससे लगे गोदाम की तलाशी ली, जहां अवैध धान का भंडारण पाया गया। व्यापारी के पास धान के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं थे। ऐसे में मंडी विभाग ने 50 बोरी अवैध धान जब्त कर लिया और छोटे व्यापारी के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

बंधवाभाठा गांव से लापता हुए वृद्ध का तालाब में मिला शव

कोरबा। बांधवाभाठा गांव के तालाब में घर से लापता हुए वृद्ध का शव मिला। मामले में पुलिस जांच कर रही है। उरगा थाना अंतर्गत ग्राम बंधवाभाठा गांव में स्थित तालाब में मंगलवार की सुबह निस्तार के लिए पहुंचे ग्रामीणों को पानी में एक व्यक्ति की लाश नजर आई। गांव में जानकारी देने पर हड़कंप मच गया। लोग घरों से निकलकर तालाब के पास पहुंचे। उरगा थाना में सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक के शव को बाहर निकाला गया तो मृतक की शिनाख्त डोंगरीभांठा निवासी 85 वर्षीय पंचराम के रूप में हुई। पंचराम के परिजन के मुताबिक पंचराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जो परिवार को घर से बिना बताए कहीं निकलकर लापता हो गए थे। परिजन वृद्ध की पतासाजी कर रहे थे और उरगा थाना में भी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।

गुरिल्ला युद्ध में माहिर, चार-स्तरीय सुरक्षा घेरे में था हिड़मा

छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश के बार्डर पर एक दिन पहले हुआ था हिड़मा का इनकाउंर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। गुरिल्ला युद्ध में माहिर हिड़मा एके-47 राइफल रखने के लिए जाना जाता था। उसकी विशाल टुकड़ी के सदस्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते थे। जंगलों के अंदर उसकी चार-स्तरीय सुरक्षा घेरे के कारण वह वर्षों तक लापता रहा। उसकी मौत के समय उस पर एक करोड़ रुपये से अधिक का इनाम था। हिड़मा 1990 के दशक के अंत में एक जमीनी स्तर के आयोजक के रूप में संगठन में शामिल हुआ था। उसने पिछले दो दशकों में कई हमलों की साजिश रची और 2010 में ताड़मेटला (दंतेवाड़ा) हमले के बाद सबसे वांछित माओवादियों में शामिल हो गया। इस हमले में 76 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। उसने तब हमले को अंजाम देने में एक अन्य शीर्ष माओवादी कमांडर पापा राव की मदद की थी। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि 51 वर्षीय हिड़मा ने कई वर्षों तक माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व किया था, जो दंडकारण्य और बस्तर के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में संगठन का सबसे मजबूत सैन्य गठन था।

26 से अधिक बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहा हिड़मा बस्तर क्षेत्र से माओवादी शीर्ष नेतृत्व में शामिल एकमात्र जनजातीय सदस्य था। वह देश के सबसे भयावह और कुख्यात उग्रवादी कमांडरों में से एक माना जाता था। सुरक्षाबलों का मानना है कि हिड़मा के मारे जाने से माओवादियों को गहरा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका लगेगा।

आदिवासी युवा शहरी नक्सलियों का शिकार न बनें

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा कि निर्दोष आदिवासी युवाओं को शहरी नक्सलियों का शिकार नहीं बनना चाहिए और अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। हथियार उठाकर उन्होंने निर्दोष दलितों और आदिवासियों की हत्या की है। उन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या की है। माओवादियों के पास सिर्फ चार महीने बचे हैं। हमारा लक्ष्य मार्च 2026 तक माओवादियों का सफाया करना है। अमित शाह एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। संजय कुमार ने कहा, माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य हिड़मा और उसकी पत्नी को आखिरकार क्या हासिल हुआ,एसी कमरों में आलीशान जिंदगी जी रहे शहरी नक्सलियों के बहकावे में आकर अपनी (आदिवासी युवाओं की) जान मत गंवाओ।

मार्च की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का सफाया संभव

देश के सबसे वांछित नक्सलियों में शामिल माडवी हिड़मा के सफाए को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल-विरोधी मोर्चे में बड़ी कामयाबी मान रही हैं। सूत्रों का कहना है कि नक्सलवाद के विरुद्ध मौजूदा अभियान की गति देखते हुए यह संभव है कि मार्च, 2026 की तय समय सीमा से पहले ही देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से माओवादी समस्या के उन्मूलन के लिए 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तय की है। एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों में लगे शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को 30 नवंबर से पहले हिड़मा को खत्म करने का निर्देश दिया था। इससे 12 दिन पहले ही उसे मार गिराया गया।

रेलवे स्टेशनों और पार्किंग में त्रिनयन एप से होगी गाड़ियों की जांच

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सभागार में रेलवे सुरक्षा से संबंधित संयुक्त बैठक हुई। इसमें पुलिस अधीक्षक जीआरपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहीं और जिला पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारी भी संयुक्त रूप से उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और परिसर पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधों की रोकथाम करना और बदलते समय में उभर रही चुनौतियों के प्रति प्रभावी व त्वरित प्रतिक्रिया विकसित करना रहा। आईजी गर्ग ने कहा कि रेलवे स्टेशन एवं परिसर की सुरक्षा, यात्री विश्वास से सीधे जुड़ी है। जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस का आपसी तालमेल मजबूत होगा, तभी हम अपराध नियंत्रण के लक्ष्य को दक्षता से प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने रेलवे स्टेशनों और पार्किंग क्षेत्रों में जांच सशक्त एप के माध्यम से वाहनों की जांच को अनिवार्य करने, त्रिनयन एप का अधिकाधिक उपयोग करने तथा साइबर प्रहरी के माध्यम से व्यापक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उन्होंने सभी एजेंसियों को समन्वित संयुक्त कार्रवाई, विशेष निगरानी और नियमित चेकिंग अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही, ऐसे मामलों का विश्लेषण करते हुए यह भी रेखांकित किया कि अपराधी अक्सर रेलवे मार्ग का उपयोग कर फरार होते हैं, अतः इन मार्गों पर ट्रैक-बेस्ड मॉनिटरिंग और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत किया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आरपीएफ और जीआरपी द्वारा टिकट काउंटरों और प्लेटफॉर्म क्षेत्रों और परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, स्थानीय पुलिस व बीडीएस टीम के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल, साइबर अपराधों से बचाव के लिए नियमित जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में एएसपी दुर्ग अभिषेक झा, एएसपी बालोद मोनिका ठाकुर, डीएसपी शिल्पा साहू मौजूद थे।

सड़क हादसे में पांच की मौत, फिल्म देखकर घर लौट रहा था परिवार

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोंडागांव। बड़े डोंगर में रहने वाला एक परिवार स्कॉर्पियो में सवार होकर बीती रात फिल्म देखने के लिए कोंडागांव आया हुआ था। जहां से वापस जाने के दौरान अचानक उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए।

घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल कोंडागांव लाया गया, जहां से 2 को उपचार के लिए मेकाज रेफर किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोंडागांव थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान ने बताया कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जो कोंडागांव से देर रात बड़े डोंगर के लिए निकली थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित मसोरा टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से जा टकराई। इस घटना में स्कॉर्पियो सवार पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए, इन घायलों में दो की स्थिति ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कार्पियो सवार सभी लोग देर रात कोंडागांव थिएटर में फिल्म देखने के लिए आए हुए थे। रात करीब 12 बजे फिल्म खत्म होने के बाद वापस बड़े डोंगर जा रहे थे। ये सभी भैसाबेडा बड़ेडोंगर क्षेत्र के निवासी हैं, वहीं स्कॉर्पियो में करीब 13 लोग सवार थे।

मृतकों मे लखन मण्डावी, भूपेंद्र मण्डावी, रूपेश मण्डावी, नूतन मांझी , शत्रुघ्न मांझी शामिल हैं।

बीएसएनएल टॉवर से जनरेटर चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क स्थित बीएसएनएल टॉवर से जनरेटर चोरी की वारदात में पुलिस ने दो चोरों और एक पिकअप चालक को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किया हुआ जनरेटर, मोटरसाइकिल, पिकअप वाहन और हाइड्रा वाहन जब्त किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

बीएसएनएल के कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी मुकेश कुमार सिदार ने 15 नवंबर को थाना पूंजीपथरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क स्थित बीएसएनएल टॉवर से 12 नवंबर को जनरेटर चोरी हो गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध पिकअप वाहन की पहचान की। वाहन की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस ने पिकअप चालक पनबुडी कुजूर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने तीन अन्य आरोपियों का नाम लिया, जिनमें अमित, दुर्योधन उरांव और कालीचरण निषाद शामिल थे। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्योधन उरांव ने पुलिस को बताया कि उसने जिंदल पार्क के बीएसएनएल टॉवर में जनरेटर देखा और उसे चोरी करने की योजना बनाई। पुलिस ने इस मामले में दुर्योधन उरांव (24 साल), कालीचरण निषाद (कलमा चंद्रपुर), और पिकअप चालक पनबुडी कुजूर (जगतपुर रायगढ़) को गिरफ्तार किया है। हालांकि, चोरी में शामिल अमित फरार है।

मिर्ची पाउडर आंख में झोंक कर लूटे जेवर, नौ महीने बाद पकड़ाए

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र में आंख में मिर्ची पाउडर झोंक कर लूट की वारदात हुई है। घटना 22 फरवरी की है। ग्राम टेकापार में तीन अज्ञात आरोपियों ने युवक की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और उसके बैग से लगभग 96 हजार रुपए के सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी नागपुर (महाराष्ट्र) का रहने वाला है, जिसने लूट के गहनों को नागपुर के ही सोना व्यापारी को बेचने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग एक लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर, बाइक और चाकू बरामद किया है। बता दें टेकापार (बोरी) के रहने वाले महेंद्र सोनी ने 22 फरवरी 2025 को बोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भतीजे राहुल सोनी के साथ ग्राम रुहा में फेरी लगाकर वापस लौट रहे थे। जब वे ग्राम टेकापार-खिलौरा के कच्चे रास्ते पर पहुंचे, तभी तीन अज्ञात आरोपियों ने राहुल की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और उसके बैग से लगभग 96 हजार रुपए के सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी बीच सूचना मिली कि लूटा गया सामान परपोड़ी क्षेत्र के कुछ लोगों को बेचा गया है। इस आधार पर पुलिस ने संदेही कपिल साहू (खालेपारा) और आकाश श्रवण (इंदिरा नगर) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपराध स्वीकारते हुए बताया कि उन्होंने अपने तीसरे साथी गणेश धनकर उर्फ चिंटू (नागपुर निवासी) के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तीनों ने लूट के आभूषण आपस में बांट लिए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़े जाने के डर से चुराया गया अधिकांश सामान गणेश धनकर लेकर नागपुर चला गया, जहां वह इसे बेचने की योजना बना रहा था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लूट में शामिल अन्य व्यक्तियों और शेष सामान की तलाश जारी है।

गांजा तस्करी केस का फरार आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर उदय जैन को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। उदय जैन के खिलाफ दो दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं और उस पर जिला बदर व एनएसए जैसी कठोर कार्रवाई भी हो चुकी है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। टिकरापारा थाना क्षेत्र में 5 नवंबर 2025 को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को रंगे हाथ गांजा के साथ पकड़ा था। उस समय आरोपियों के पास से 23.014 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 2.30 लाख रुपये आंकी गई, जब्त किया गया था। साथ ही एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी। गिरफ्तार आरोपी में प्रतीक शर्मा, मोहम्मद शमीम, शेख सारुख उर्फ शाहरूख ,पलक नागवानी उर्फ मिस बच्ची शामिल थे।

पूछताछ के दौरान पता चला कि इस नेटवर्क का मुख्य संचालक उदय जैन फरार है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उदय जैन की लोकेशन उड़ीसा में ट्रेस की और वहां दबिश दी। उसे वहीं से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। उसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनके जरिए वह नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। उदय जैन खमतराई थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। उस पर हत्या का प्रयास, नारकोटिक्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मारपीट समेत 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ जिला बदर, एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून),पीआईटी एनडीपीएस कार्रवाई भी हो चुकी है, जिसके तहत वह पहले जेल में निरुद्ध रह चुका है।

बंधक बनाकर डकैती, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। जिले के मुजगहन थाना क्षेत्र के कमल विहार स्थित कृष्णा हाइट्स में बंधक बनाकर की गई डकैती की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने दो महिला, दो युवक और एक अपचारी बालक सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पूजा सचदेव हत्या, मारपीट, आबकारी और नारकोटिक्स एक्ट जैसे दर्जनभर मामलों में पहले भी जेल जा चुकी है। घटना 14 नवंबर की रात की है।

पीड़िता रोशिता तिर्की अपने भाई के फ्लैट में गई थी। जब वह वापस लौट रही थी, तभी बिल्डिंग के बाहर पूजा सचदेव और उसके साथ मौजूद तीन पुरुष व एक महिला ने खुद को पुलिस बताते हुए पीड़िता और उसके भाई-बहन को रोक लिया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए सभी को कमरे में ले जाकर चाकू की नोक पर रस्सी से बांध दिया, और एटीएम कार्ड का पिन लेकर कैश निकाल लिया। इसके बाद लैपटॉप, गैस सिलेंडर और दोपहिया वाहन लूटकर फरार हो गए। डकैती को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एसीसीयू और थाना मुजगहन की संयुक्त टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर छापेमारी शुरू की। टीम ने आरोपित पूजा सचदेव, आसीमा राव, निखिल सचदेव, अंकित सोनी और एक अपचारी बालक को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सभी ने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दोपहिया वाहन (1 नग), गैस सिलेंडर, लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, बर्तन, 15 हजार रुपये नकद,एटीएम कार्ड और वारदात में प्रयुक्त बाइक मिलाकर करीब 2.20 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया है। कुछ अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 251/25, धारा 310(2), 74 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

कार्यालय जिला पंचायत बालोद

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" जिला बालोद के जनपद पंचायत स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु विज्ञापन दिनांक 14.11.2025 जारी करते हुए दिनांक 05.12.2025 तक आवेदन पत्र आमत्रित किये गये है। विज्ञापन का विस्तृत्त अवलोकन बालोद जिले के वेब-साइट www. balod. gov.in एवं www. bihan. gov.in पर किया जा सकता है एवं आवेदन पत्र प्रारूप को डाउनलोड भी किया जा सकता है।

S-45949/3

नाम परिवर्तन

मैं राजीव अग्रवाल पिता स्व. जगदीश प्रसाद अग्रवाल उम्र 50 वर्ष, निवासी-बी-79 गौरव पाथ, आम्रपाली वनांचल सिटी हाउसिंग बोर्ड, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं जो कि निम्न लिखित कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत करता हूं। यह कि मेरी जन्मतिथि 10.05.1975 है जो कि सही एवं सत्य है। यह कि मैं पूर्व में अपना नाम RAJIV AGGARWAL लिखता था अब मैंने अपने नाम की वर्तनी में परिवर्तन करते हुए इसे RAJIV AGRAWAL कर लिया है। यह कि भविष्य में सभी प्रकार दस्तावेजों, अभिलेखों, पहचान पत्र, बैंक रिकार्ड तथा अन्य सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यो में मेरा नाम RAJIV AGRAWAL ही मान्य होगा।

राजीव अग्रवाल
बी-79 गौरव पाथ,
आम्रपाली वनांचल
सिटी हाउसिंग बोर्ड, भिलाई,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने स्थापित किए कई कीर्तिमान, सीएम साय बोले-

2047 तक इसी बुनियाद पर बनेगा विकसित छत्तीसगढ़

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र के समापन अवसर पर कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है। यह विधानसभा भवन केवल एक परिसर नहीं है, यह हमारे छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ निवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस भवन से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अब तक के सभी सदस्यों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यह संविधान का अमृत वर्ष है। हमें अपने संविधान को आत्मार्पित किए 75 वर्ष हो गए हैं, ऐसे में यह अवसर संवैधानिक मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करने वाली विभूतियों के स्मरण का भी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह विधानसभा भवन अंत्योदय और जनकल्याण की उपलब्धियों का साक्षी रहा है। सभी सदस्यगणों ने अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिभा के साथ इस विधानसभा भवन में जो कड़ी मेहनत की है, वह अविस्मरणीय रहेगी। उन्होने कहा कि विधानसभा के इस भवन में जो विधेयक पारित हुए हैं, जो कानून बनाये गए हैं, उनके माध्यम से आज 25 वर्षों की गौरवशाली संसदीय यात्रा में समृद्ध छत्तीसगढ़ की नींव तैयार हुई है। श्री साय ने कहा कि राज्य बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र का आयोजन राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में हुआ था और उसके बाद इस भवन में विधानसभा शुरू हुई। फिर अनेक गौरवशाली पलों का यह विधानसभा भवन साक्षी रहा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु तक अनेक गणमान्य अतिथियों की यहां उपस्थिति एवं प्रेरक सम्बोधनों ने संवैधानिक परम्परा को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वरूप को निखरते हुए सभी सदस्यों ने देखा है। कैसे न्यूनतम साधनों से छत्तीसगढ़ महतारी के सपूतों ने इन पच्चीस बरसों में छत्तीसगढ़ को संवारा है। प्रत्येक सदस्य इस बात के गवाह है। विधानसभा का यह भवन छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। लोकतंत्र के इस मंदिर की बहुत सारी स्मृतियां, यहां के सत्र, तीखी और मीठी नोंक-झोंक, सबकुछ इस परिसर ने देखा है और यह दस्तावेज के रूप में संकलित है।

26 लाख से अधिक पीएम आवास स्वीकृत

सीएम साय ने कहा कि इस विधानसभा भवन ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2023 में जब हमारी सरकार बनी, तो सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी फाइल को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। घर भी बने और घर के अंदर रसोई भी बदली। चूल्हे की जगह उज्ज्वला सिलेंडर प्रदान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज विधानसभा के विशेष सत्र के समापन अवसर पर कहा कि' सत्ता पक्ष की ओर 15 और विपक्ष की ओर से 10 सदस्यों इस तरह 25 वर्ष की विकास यात्रा में संयोग से 25 माननीय सदस्यों ने सदन में विशेष सत्र में अपनी बात रखी। मुझे इस बात की खुशी है कि जिसकी बुनियाद हमारे पुरोधाओं ने रखी थी उसकी मर्यादा को यहाँ माननीय सदस्यों ने क़ायम रखा। उन्होंने कहा कि प्रेम प्रकाश पांडेय जी के विधानसभा अध्यक्ष रहते क्लोज़ डोर मीटिंग हुई। यह सदन केवल क़ानून नहीं बनाता बल्कि बेहतर भविष्य बनाता है। दिसम्बर 2023 को मेरे सार्वजनिक जीवन का वह क्षण था, जिसे मेरे लिए शब्दों में बाँध पाना संभव नहीं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने आगे कहा कि आज जो दायित्व निभा रहा हूँ वह बड़ा दायित्व है। मैं इसके काबिल बनने का प्रयास कर रहा हूँ । विधानसभा अध्यक्ष का पद शक्ति का नहीं, उत्तरदायित्व का है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान बनी है। उनके नेतृत्व में राज्य और मुझे लगता है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या माओवाद आतंक का समाधान होने जा रहा है । विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य ब्याज दर मिलने और सड़क का नेटवर्क यही से पास हुआ । मेडिकल कॉलेज सहित जनहित के सभी विकास कार्यों और कार्यक्रमों का निर्णय यही से हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। उन्होंने रजत जयंती वर्ष में विधानसभा के विशेष सत्र के समापन अवसर पर सदस्यों और मीडिया के साथियों ने सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद दिया।

25 वर्षों की जनाकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य स्थापना के रजत महोत्सव के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों छत्तीसगढ़ के नये विधानसभा परिसर का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ''यह केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जनाकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में देश स्वर्णिम शिखर की ओर बढ़ा और एक नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के रूप में और हमारा यह विधानसभा अस्तित्व में आया। स्व. बाजपेयी ने राज्य का निर्माण तो किया ही, साथ ही केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने की महती योजना तैयार की, जिसका इसका भरपूर लाभ छत्तीसगढ़ को मिला। छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में आपने और हमारे विधानसभा के साथियों ने बहुत पसीना बहाया है। सबको खाद्य सुरक्षा दिलाने की आपकी पहल से प्रदेश के लाखों लोगों को भूख से मुक्ति मिली। छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल को देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया। धान खरीदी के व्यवस्थित मॉडल से लाखों किसानों को पहली बार अपने फसल का बढ़िया मूल्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्रीसाय ने कहा कि विधानसभा नीति निर्माण का मंच होने के साथ सामाजिक सुधार का सेतु भी है। इसी विधानसभा भवन में मातृ शक्ति के सम्मान को सुरक्षित रखने टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, शासन और लोक सेवकों की जनता के प्रति जवाबदेही तय करने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक तथा युवाओं को कौशल विकास का अधिकार प्रदान किया गया। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास को डबल इंजन की सरकार से शक्ति मिल गई और चहुँओर ऐसे कार्य आरंभ हुए, जिससे छत्तीसगढ़ के विकास का ग्राफतेजी से उत्तरोत्तर चढ़ता गया।

छत्तीसगढ़ का हर किसान उम्मीद से भरा

मुख्यमंत्री साय ने विधान सभा में कहा कि विधानसभा भवन को हमने धान की बालियों से सजाया है। छत्तीसगढ़ का हर किसान उम्मीद से भरा है, क्योंकि पर्याप्त पानी है, बिजली है और उनके उत्पादन का उचित मूल्य है। जब किसान भरपूर मेहनत करते हैं, खूब अन्न उपजाते हैं तो एक संवेदनशील सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि किसानों के उत्पादन के अनुरूप खरीदी का स्तर भी बढ़ाये। हमने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 25 बरसों की इस यात्रा में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। विधानसभा में बैठी हुई महिला सदस्य राज्य को संवारने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। पूर्व में भी महिला सदस्यों ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा से छत्तीसगढ़ को संवारा है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में पहल करते हुए इसी विधानसभा भवन से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

विकास यात्रा को युवा शक्ति ने लगातार गढ़ा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, इस संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने विज़न डॉक्युमेंट नवा अंजोर 2047 के रूप में लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने का कि छत्तीसगढ़ की 25 बरसों की विकास यात्रा को युवा शक्ति ने लगातार गढ़ा है। इस रजत यात्रा में ऐसी अनेक संस्थाएं प्रदेश में स्थापित हुई हैं जिन्होंने प्रदेश के मानव संसाधन की प्रतिभा को उभारने में बड़ी भूमिका निभाई। हमारे यहां एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपलआईटी, आईआईएम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। यहां निफ्ट, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जैसी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं भी यहां आरंभ किया जा रहा है। हमारा नवा रायपुर आधुनिक भारत की सबसे नई बसाहट है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई तथा नवा रायपुर को मिलाकर हमने स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है। यह आईटी हब, फार्मा हब, टैक्सटाइल हब के रूप में उभरेगा।

हर घर बिजली पहुंचाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्षों में हमने हर घर बिजली पहुंचाई है। अब लोग प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं। इसी विधानसभा में पिछले दो साल में ज्ञान और गति आधारित ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस सदन द्वारा जनविश्वास विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, नगर पालिका तथा नगर निगम संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय स्थापना संशोधन विधेयक, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक और भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक समेत अनेक जनकल्याणकारी विधेयक पारित किए गए।

समृद्धि छत्तीसगढ़ की हुई नींव तैयार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 25 बरस पहले जब हमने विधानसभा की यात्रा आरंभ की थी, तब हम सभी अपने साथ अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा की गौरवशाली परंपराएं लेकर आये थे। हमने हर श्रेष्ठ संसदीय परंपरा का पूरी प्रतिबद्धता से निर्वहन किया है। अविभाजित मध्यप्रदेश की विधानसभा में जिन सुंदर विधायी परंपराओं का निर्माण हुआ, मुझे भी अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें गर्व है कि सभी श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को इस विधानसभा भवन ने समृद्ध करने का काम किया है।

बस्तर के गांवों में नया आत्मविश्वास उत्पन्न

साय ने कहा कि माओवाद की वजह से पिछड़ गये बस्तर जैसे इलाकों के लिए यहां से विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। नियद नेल्ला नार योजना, पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम अभियान, जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से बस्तर विकसित छत्तीसगढ़ के आकाश में नक्षत्र की तरह उभरने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल उन्मूलन पर बात करते हुए कहा कि बीते महीनों में सैकड़ों नक्सलियों का आत्मसमर्पण, टॉप कैडर की गिरफ्तारियाँ और लगातार सफल ऑपरेशन्स यह संकेत देते हैं कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है। नियद नेल्ला नार, नक्सलियों के पुनर्वास की प्रभावी नीति और नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना ने जनविश्वास को अत्यधिक मजबूत किया है

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली का लाभ

मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफबिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय न केवल जनता के बिजली बिल को कम करेगा बल्कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं वैचारिक भिन्नता के बावजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मर्यादित और संसदीय आचरण की श्रेष्ठता को बरकरार रखा है। यह देश की अन्य विधानसभाओं के लिए अनुकरणीय है।

जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार

छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ पंचायत और सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में मिला सम्मान, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ को मिला पुरस्कार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल संचय, जन भागीदारी श्रेणी में भी छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट राज्य का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं, नगरीय निकाय श्रेणी में रायपुर नगर निगम को प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा पूर्वी जोन के जिलों में विभिन्न श्रेणियों में बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर एवं रायगढ़ को भी जल संचय, जन भागीदारी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय जलमंत्री सीआर पाटिल भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय जल पुरस्कारों पर सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा यह सम्मान राज्य में जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के प्रति हमारी निरंतर मेहनत का परिणाम है।

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया गया।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक नई पहल शुरू की है, जल संचय, जन भागीदारी। इसके तहत भी इस वर्ष पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट राज्य का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ से जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं, नगरीय निकाय श्रेणी में रायपुर नगर निगम को देश में प्रथम स्थान मिला है। निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा पूर्वी जोन के जिलों में विभिन्न श्रेणियों में बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर एवं रायगढ़ को भी जल संचय, जन भागीदारी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्यूए) की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जल के महत्त्व से अवगत कराने और उन्हें बेहतर जल उपयोग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा पूरे देश में जल संरक्षण, जल प्रबंधन और 'जल समृद्ध भारत' के सरकार के विज़न को साकार करने के लिए किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों को सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देना, जागरूकता फैलाना और समाज को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है।

छत्तीसगढ़ को एक साथ तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार तथा 'जल संचयङ्कजन भागीदारी' श्रेणी में उत्कृष्ट राज्य का द्वितीय स्थान मिलना हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि हमारे किसानों, पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, नगरीय निकायों, जल संसाधन विभाग, समाज के जागरूक नागरिकों और जनभागीदारी से आगे बढ़े जल संरक्षण जनआंदोलन का प्रतिफल है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों यह सम्मान मिलना हमारे प्रयासों को और सशक्त करता है। छत्तीसगढ़ सरकार जल संसाधनों के संरक्षण, पुनर्भरण और सतत प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 'जल समृद्ध छत्तीसगढ़' के संकल्प को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। — **मुख्यमंत्री विष्णु देव साय**

प्रदेश का जल भविष्य सुरक्षित करने में यह पुरस्कार होगा प्रेरणादाईः मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जल संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर छत्तीसगढ़ के दो जिलों रायपुर और बालोद ने राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रच दिया है। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जनभागीदारी 1.0 अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दोनों जिलों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासनिक प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण की दिशा में देशभर में विशेष पहचान बनाई है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के अभिनव प्रयासों और जनभागीदारी ने जल संचयन की दिशा में नए आयाम हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के नागरिकों और प्रशासन को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जल संचयन के प्रति लोगों में आई यह चेतना जल के समुचित उपयोग को बढ़ावा देगी और जल का अनावश्यक दोहन कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का जल भविष्य सुरक्षित करने में यह पुरस्कार प्रेरणादाई होगा और जनभागीदारी बढ़ने से हम जल संचयन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।

रायपुर जिले को जल संचय जनभागीदारी 1.0 अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने ग्रहण किया। देशभर के नगर निगमों में रायपुर नगर निगम प्रथम स्थान पर रहा, जबकि ईस्टर्न जोन कैटेगरी 01 में रायपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा। रायपुर जिले और नगर निगम ने मिलकर सामुदायिक सहभागिता को जल संचय का व्यापक अभियान बनाया। रायपुर नगर निगम द्वारा 33,082 कार्य और जिला प्रशासन द्वारा 36,282 कार्य तथा राज्य स्तर पर कुल 4,05,563 जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए। इनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स, अमृत सरोवर, टॉप डैम एवं परकुलेशन टैंक शामिल हैं। रायपुर में 4 एसटीपी के माध्यम से 206 एमएलडी क्षमता विकसित की गई है। 09 औद्योगिक इकाइयों को 125.849 एमएलडी शुद्ध जल आपूर्ति की जा रही है। प्रत्येक वार्ड में वर्षा जल संचयन, 20 से अधिक सरोवरों का पुनर्जीवन और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से स्मार्ट ग्राउंडवॉटर मॉनिटरिंग ने इस उपलब्धि को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित दूसरे जिले बालोद को पूर्वी जोन में बेस्ट परफॉर्मिंग जिला घोषित किया गया, जिसके साथ 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। यह सम्मान कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने ग्रहण किया।

कलेक्टर मिश्रा ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अमले और संपूर्ण बालोदवासियों को दिया। बालोद जिले ने 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तहत प्रभावशाली और बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कार्य किए। इसके तहत 1 लाख 6 हजार 677 नई जल संरचनाएँ निर्मित की गई। 30 हजार 849 पुराने जल स्रोतों की मरम्मत व सफाई, प्रधानमंत्री आवासों में 10 हजार वाटर रिचार्ज पिट, वन क्षेत्र में 3 लाख 88 हजार पौधरोपण, 27 हजार से अधिक घरों में स्वयं प्रेरित सोकपिट निर्माण, 1 लाख 09 हजार 27 स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच, 140 अमृत सरोवर, 6 हजार 160 निजी डबरी, 1 हजार 944 सामुदायिक तालाब, 399 मिनी परकुलेशन टैंक, 6 हजार 614 लूज बोल्डर चेक डैम, 69 स्टॉप डैम, 316 गेबियन चेक डैम, 423 कुएं निर्मित किए गए हैं। ये विस्तृत कार्य बालोद की जल संरक्षण नीतियों और जनता की सक्रिय भागीदारी की मिसाल हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950